सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-33 अंक-14 | 22 जुलाई से 5 अगस्त, 2018 | मुख्य संपादक कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ 8 | मूल्य : 2 रुपये

विश्व सर्वहारा के महान नेता
फ्रेडरिक एंगेल्स लाल सलाम

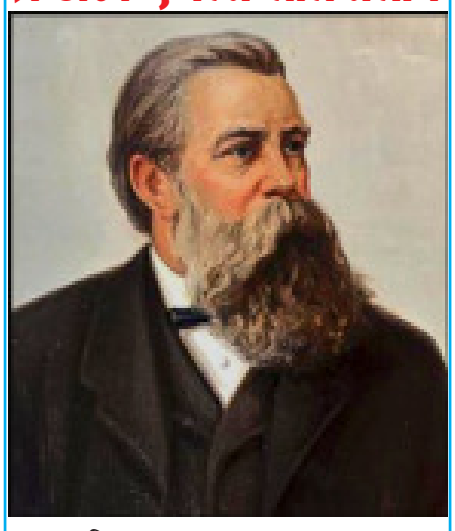

5 दिसम्बर 1820- 5 अगस्त 1895

''ईसाई धर्म और मजदूरों का समाजवाद दोनों ही गुलामी और दुख-दर्द से आसन्न मुक्ति का संदेश देते हैं। ईसाई धर्म कहता है कि यह मुक्ति अगले जीवन में, मृत्यु के बाद स्वर्ग में प्राप्त होगी; समाजवाद कहता है कि वह इसी दुनिया में, समाज को बदल कर मिलेगी।'' – **एंगेल्स**

(प्रारम्भिक ईसाई धर्म का इतिहास)

सर्वहारा के महान नेता, इस युग के अग्रणी मार्क्सवादी चिंतनकार
कॉमरेड शिवदास घोष की 42वीं मृत्यु वार्षिकी सम्मानपूर्वक मनायें

5 अगस्त को सर्वहारा, मजदूर-किसानों, मेहनतकशों के महान नेता, शिक्षक, पथ प्रदर्शक, इस युग के एक अग्रणी मार्क्सवादी चिन्तनकार एवं एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के संस्थापक महासचिव कॉमरेड शिवदास घोष की 42वीं बरसी है। 5 अगस्त 1976 को इंदिरा कांग्रेस द्वारा थोपे गए आपातकाल के बेहद दमघोंटू माहौल में भयंकर हृदयाघात से कामरेड घोष की मृत्यु हो गई थी। 5 अगस्त को हर साल देश के कोने-कोने में उनकी याद में जनसभाएं की जाती हैं और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाती है। पार्टी के नेता-कार्यकर्ता और उन्हें मानने वाले हजारों-हजार लोग सभी इस दिन उनके बताए मार्ग पर चलने के अपने संकल्प को तरोताजा करते हैं।

इस साल जब हम यह स्मृति सभा करने जा रहे हैं तो देश-प्रदेश के हालात बेहद असहनीय हैं। पिछले 4 साल के शासन के दौरान भाजपा ने विदेशों से काला धन वापस लाने, हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देने, किसानों के कर्जे माफ करने, अच्छे दिन लाने समेत किसी भी वादे को नहीं निभाया। उल्टे, पूंजीपतियों का मुनाफा इस हद तक बढ़ा दिया कि अम्बानी एशिया का सबसे बड़ा अमीर बन गया है। महंगाई और बेरोजगारी बेशुमार

बढ़ी है। हर रोज डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाने के अलावा बिजली-रेट, बस-किराये, रेल भाड़े बढ़ाए हैं। जबरन नोटबंदी करके पूरे देश को बरगलाया और गरीब आम आदमी को नाजायज तंग करने के साथ-साथ भारी संख्या में उनके रोजगार छीन लिए। सरकारी शह से बैंकों में लूट व भ्रष्टाचार की हद हो गई। चन्द बड़े पूंजीपतियों ने सरकारी बैंकों से 13 लाख करोड़ रुपये हड़प लिए हैं। जीएसटी व एफडीआई थोप कर दुकानदारों व छोटे कारोबारियों को संकट में डाल दिया है। मनरेगा को करीबन समाप्त कर दिया। खेती में गरीब, छोटे व मध्यम किसान तबाह हो रहे हैं। उन्हें अपनी फसल के लाभकारी दाम नहीं मिलते। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राईवेट कम्पनियों के स्वार्थ में बनाई गई है। मजदूरों से 12-12 घंटे काम कराया जाता है, फिर भी 18000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन लागू नहीं किया। लाखों पद समाप्त कर नौकरी के अवसर खत्म कर दिए। पात्रता परीक्षा पास करने पर भी हजारों युवा रोजगार से वंचित हैं। भर्ती के नाम पर तमाशा बना रखा है। शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हैं। सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक परीक्षा प्रणाली समाप्त करने से शिक्षा का स्तर रसातल में है। चौतरफा शोषण-उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं है। महिलाओं, छात्राओं, बच्चियों पर भी जुल्म की अति हो रही है। हर राज्य में यही स्थिति है।

राजनैतिक हालात भी समान रूप से दमघोंटू हैं। कांग्रेसी शासन की तर्ज पर वर्तमान भाजपा सरकार देश में फासीवाद थोपने की

(शेष पृष्ठ 7 पर)

पहली कक्षा से पास-फेल प्रणाली पुनः लागू करने की मांग पर
संसद पर विशाल प्रदर्शन

नई दिल्ली : यूपीए सरकार द्वारा लागू की गई और वर्तमान बीजेपी-नीत एनडीए सरकार द्वारा आगे बढ़ायी जा रही सरकारी स्कूलों में बेरोकटोक पास करने की नीति के खिलाफ एसयूसीआई (सी) के सैकड़ों कार्यकर्ताआ, समर्थकों और शिक्षा प्रेमी लोगों ने यहां 18 जुलाई को विरोध प्रदर्शन किया। 2009 में लागू होने से लेकर आज तक इस नीति ने पूरे देश में स्कूल शिक्षा के प्राथमिक स्तर में (पहली से आठवीं कक्षा तक) पठन-पाठन प्रक्रिया को तबाह कर दिया है और स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वालों (ड्रॉप-आउट्स) की संख्या खतरनाक हद तक पहुंच गई है। जुलूस मंडी हाउस से शुरू हुआ जो संसद मार्ग पर पहुंच कर सभा में तब्दील हो गया। पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य एवं हरियाणा राज्य सचिव कॉ. सत्यवान मुख्य वक्ता थे।

सभा को पार्टी के दिल्ली राज्य सचिव कॉ. प्राण शर्मा, पंजाब प्रभारी कॉ. अमिन्द्रपाल सिंह, पार्टी की उ.प्र. राज्य कमेटी सदस्य कॉ. विजयपाल सिंह, शिक्षा बचाओ कमेटी के दिल्ली अध्यक्ष प्रो. नरेन्द्र शर्मा, एआईडीएसओ, दिल्ली राज्य अध्यक्ष कॉ. प्रशांत और सतेंद्र मौर्य ने भी सम्बोधित किया। मंच संचालन कॉ. रमेश शर्मा ने किया।

वक्ताओं ने संसद के मानसून सत्र में एक विधेयक पेश करने के पीछे केंद्र सरकार के इरादे के बारे में मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए बताया कि केवल 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के छात्रों के मामले में ही 'नो डिटेन्शन' पॉलिसी में चुनीन्दा कुछ बातों को रद्द करने के लिए 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009' के प्रावधानों में संशोधन किये जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि पहली से चौथी कक्षा तक के छात्रों और छठी-सातवीं कक्षा के छात्रों के मामले में यही नीति के निरंतर में चालू रहेगी। वक्ताओं ने इसे क्रूर मजाक कहा क्योंकि इससे ड्रॉप-आउटों की बढ़ती रफ्तार को कम करने के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उल्टे ड्रॉप-आउटों की संख्या अब 5वीं कक्षा के स्तर पर बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यूनेस्को 2016 रिपोर्ट से यह काफी हद तक साबित हो चुका है। इस रिपोर्ट के अनुसार 10वीं कक्षा में वार्षिक ड्रॉप-आउट छात्रों की संख्या की दर बढ़ कर 4 करोड़ 70 लाख हो गई है। 'नो डिटेन्शन' पॉलिसी का दूसरा दुष्परिणाम यह है कि सरकार द्वारा संचालित और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शैक्षिक वातावरण (यानी, पढ़ने-पढ़ाने का ढर्रा) बेहद खतरे में पड़ गया है। सीएबीई (शिक्षा पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड) की बैठकों में इसकी पुष्टि बार-बार हुई है। इस तरह केंद्र व राज्य सरकारें बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। इन संस्थानों में दी जा रही शिक्षा का स्तर आये दिन बद से बदतर होता जा रहा है। शिक्षा के स्तर में तेजी से आ रही गिरावट के कारण अभिभावक, अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति के बावजूद, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजने को मजबूर हैं, जो भारी मुनाफा कमा रहे हैं।

वक्ताओं ने केंद्र सरकार से इस संबंध में नीति की समीक्षा करने और 'नो डिटेन्शन पॉलिसी' को वापस लेने का आग्रह किया, जिसका अर्थ दूसरे शब्दों में यह है कि कक्षा-1 से पास-फेल प्रणाली फिर से चालू की जाए। बाद में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शास्त्री भवन में मानव संसाधन विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपा।

दिल्ली : कक्षा 1 से पास-फेल प्रणाली लागू करने की मांग पर सड़कों पर उतरे एसयूसीआई (सी) कार्यकर्ता, समर्थक एवं शिक्षाप्रेमी लोग

सच्चे वामपंथ का पुनरुत्थान ही है आरएसएस-बीजेपी गठजोड़ को परास्त करने का एकमात्र तरीका

– एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के 70वें स्थापना दिवस पर गुवाहाटी, असम में आयोजित सभा में पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड असित भट्टाचार्य का भाषण

24 अप्रैल 1948 को सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष के चिंतन के आधार पर और उनके नेतृत्व में भारत की सरजमीं पर सही कम्युनिस्ट पार्टी एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की स्थापना की गई थी। पार्टी स्थापना दिवस की 70वीं सालगिरह के अवसर पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), असम राज्य कमेटी के तत्वावधान में यह सभा आयोजित की जा रही है। हम हर साल निष्ठा-लगन के साथ इस दिवस को मनाते हैं, कॉमरेड शिवदास घोष चिंतन के आधार पर ताजातरीन राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं, उन ठोस विश्लेषणों के आधार पर हमारे क्रांतिकारी कार्यों को निर्धारित करते हैं और आम मेहनतकश लोगों को शामिल करते हुए भारत में पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति को पूरा करने की प्रक्रिया को तेज करने का संकल्प लेते हैं। इसलिए, पार्टी स्थापना दिवस मनाना महज एक रस्म अदायगी नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

देश की विस्फोटक स्थिति

आप जानते हैं कि पूरा देश एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक–हर क्षेत्र में स्थिति विस्फोटक हो गई है। आर्थिक संकट चरम अवस्था में पहुंच गया है। आकाशछूती महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति की समस्या के साथ-साथ गहन आर्थिक मंदी और जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त बहुत ही घटिया किस्म का भ्रष्टाचार कहर ढा रहा है। महज जैसे-तैसे जिन्दा रहने के लिए, जैसे डूबते को तिनके का सहारा, ऐसे लोग जो कुछ मिल जाए, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि व्यर्थ में हाथ-पैर मार रहे हैं। वे आजीविका का कोई सुनिश्चित सहारा तलाश नहीं पा रहे हैं। कोई नई नौकरियां उत्पन्न नहीं होती हैं। इसके विपरीत, रोजगार के लिए जो कुछ भी गुंजाइश थी, वह भी जबरदस्त हद तक खत्म हो चुकी है। नए कल-कारखाने, उद्योग-धंधे लगने का कोई नामो निशान नहीं है। इसकी बजाय, अतीत में जो लगे थे, वे मौजूदा उद्योग भी बंद होते जा रहे हैं, एक-एक करके उनके शटर गिरते जा रहे हैं। नतीजतन, बेरोजगारी की समस्या ने विस्फोटक रूप धारण कर लिया है। देश भर में नए उद्योगों की स्थापना के लिए पूर्व शर्त–जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों, कच्चे मालों और प्रौद्योगिकी की प्रचुरता के साथ-साथ देश में शारीरिक और मानसिक श्रम शक्ति आदि सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र तेजी से गायब होता जा रहा है। लोगों को एक सभ्य जीवन सुनिश्चित करने के लिए, निर्बाध रोजगार पैदा करना सबसे आवश्यक कार्य है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाकर इस शक्ति का इस्तेमाल करके इस काम को करना बिल्कुल संभव है। लेकिन आज, घोर संकटग्रस्त पूंजीवाद ऐसा करने में असमर्थ है। पूंजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था में दुनिया भर में रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं। हाल ही में एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन अखबारों के जरिये मेरे नोटिस में आया था। चपरासी के लगभग एक हजार पदों के लिए बेरोजगारों से लाखों आवेदन प्राप्त हुए थे। उनमें से बहुत सारे तो स्नातक, स्नातकोत्तर और यहां तक कि पीएचडी डिग्रीधारी भी थे। यह कोई इक्की-दुक्की घटना नहीं है–हर जगह ऐसा हो रहा है। सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी भारी छंटनी चल रही है। स्थायी रोजगार लगभग नदारद हैं। सरकारी कार्यालयों, सरकारी क्षेत्रों, बैंकों, स्कूल-कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में किसी नये पद का सृजन नहीं किया जा रहा है। इसके बजाए, मौजूदा पदों को समाप्त कर दिया जा रहा है, और रिक्त पड़े पदों को खत्म कर दिया गया है। जो कुछ भी अन्य अनिवार्य निर्माण कार्य या छोटी-मोटी औद्योगिक गतिविधियां हो रही हैं, परिष्कृत मशीनों और स्वचालित तरीकों के बढ़ते उपयोग और उत्पादन की लागत को कम बनाए रखने के लिए श्रमशक्ति में भारी कटौती के साथ कराई जा रही हैं और इस प्रकार पूंजीपतियों को अधिकतम मुनाफा सुनिश्चित होता है। यहां तक कि मैन्युअल श्रम में भी कम वेतन पर और न्यूनतम संख्या में मजदूरों को ठेके या अनुबंध के आधार पर लगाया जाता है। अनुबंध सेवा, 'पैरा-शिक्षक', 'पैरा-प्रोफेसर', 'पैरा-डॉक्टर' आदि जिन विशेषताओं को अतीत में देखा-सुना नहीं था, आज ये आम बात हो गई हैं। 20-25 साल पहले भी, स्थिति इस तरह की नहीं थी। 'वैश्वीकरण', 'व्यावसायीकरण', 'निजीकरण' आदि के नारों के तहत देशी-विदेशी पूंजीपतियों, एकाधिकारी पूंजीपतियों द्वारा निर्मम शोषण लोगों को सम्पूर्ण विनाश, यहां तक कि मौत के मुंह में धकेल रहा है। आप जानते हैं कि हमारी आबादी का 75-80 प्रतिशत गांवों में ही रहता है। उनकी दुर्दशा अवर्णनीय है। भूमिहीन किसानों की संख्या एक खतरनाक रफ्तार से बढ़ रही है। उनकी भूमि हवा में गायब नहीं होती जा रही है बल्कि धनी किसानों या ग्रामीण बुर्जुआ के हाथों में केंद्रित

गुवाहाटी : सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. असित भट्टाचार्य

होती जा रही है। ये भूमिहीन किसान आजीविका की तलाश में शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। लेकिन उन्हें खपाने के लिए कोई नया उद्योग नहीं है। यहां तक कि पुराने लगे-लगाए उद्योग भी मौजूदा पूंजीवादी बाजार संकट से रूबरू होकर तेजी से बंद होते जा रहे हैं। इस तरह, आजीविका के किसी भी अन्य वैकल्पिक साधन के बिना, ये भूमिहीन किसान सर्वहारा किसानों या खेतमजदूरों या यहां तक कि महज अकुशल मजदूरों में ही तब्दील होते जा रहे हैं। ये भुखमरी के शिकार, अध नंगे-अधभूखे बदहाल किसान गाहे-बगाहे हर तरह के अभाव, लाचारी और हारी-बीमारी में पड़ कर बिना इलाज के अकाल मौत मर जाते हैं। निम्न-मध्यम दर्जे के किसान और गरीब किसान की हालत भी बेहद गहरे संकट में है। धनी किसानों और बड़े-बड़े आढ़तियों के जाल में फंसे होने के कारण, उन्हें अपने कृषि उपज के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। वे कर्जजाल में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं और ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। जीवन उनके लिए इतना असहनीय हो गया है कि वे आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ साल पहले 'अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी' का गठन लोगों के आय वितरण का आकलन करने के लिए किया गया था। समिति की रिपोर्ट में मुख्य रूप से पता चला कि भारत की 77 प्रतिशत आबादी केवल 20-22 रुपये ही प्रति दिन खर्च करने की स्थिति में है। उसके बाद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इसके बजाय यह और भी बदतर हो गई है। इस तथ्य से और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है कि स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी, 77% आबादी इतनी घोर गरीबी और अकल्पनीय दु:ख-तकलीफों में दिन काट रही है। यह भी पता चला है कि देश के 1% घरानों के पास देश की पूरी संपत्ति का 50% भाग है। यह कितना चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन है! इससे अधिक चिंता की बात यह है कि सही विचारधारा के आधार पर सही नेतृत्व की ओर से आवश्यक सहायता और उसके द्वारा सही मार्गदर्शन की अनुपस्थिति में आम मेहनतकश लोग अपने बढ़ते संकट और दुर्दशा के वास्तविक कारण के बारे में अंधेरे में हैं। तो, वे बस किंकर्तव्यविमूढ़ हैं और पूरी तरह से असहाय महसूस करते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या किया जाना है, जाएं तो जाएं कहां। कई मामलों में, गलत दिशा में ले जाने के लिए गलत रास्ता अपनाने को उन्हें गुमराह कर दिया जाता है और इसके नतीजतन उन्हें और भी बर्बादी की ओर धकेल दिया जाता है।

बढ़ रहा है राजनीतिक संकट

सर्वोपरि, इस तीव्र आर्थिक संकट के साथ जुड़ा हुआ है बढ़ता राजनीतिक संकट। राजनीतिक संकट के कई पहलू हैं, जिनमें से सभी की आज की बैठक में विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ, वह यह है कि सांप्रदायिकता की समस्या ने अन्य सभी ज्वलंत समस्याओं को पीछे छोड़ दिया है। यह दावानल की तरह फैल रही है। आपने देखा है कि देश भर में हर जगह सांप्रदायिकता की इस समस्या ने एक बहुत ही खतरनाक आयाम ले लिया है। सांप्रदायिकता का जहर पूरे देश में एक बहुत ही नियोजित तरीके से फैलाया जा रहा है। जाहिर है, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के आम लोगों को दंगे-फसादों, यहां तक कि खून खराबों में भी संलिप्त कर देने की लगातार सभी कोशिशें जारी हैं। कई जगहों पर, यह पाया जाता है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को राज्य के संरक्षण में गुप्त रूप से सरअंजाम दिया गया है। कुछ मामलों में, यह भी पाया जाता है कि हालांकि दोनों समुदायों के लोग दंगे-फसाद में शामिल नहीं होना चाहते हैं, फिर भी सांप्रदायिक अपराधियों को बाहर से संगठित करके दंगे-फसाद करवाये जा रहे हैं। साफ-साफ देखा जा रहा है कि निहित स्वार्थों के जरिये बेखटके सांप्रदायिकता के जहरीले बीजों को बोया जा रहा है और ऐसे अन्य फूटपरस्त विचारों को फैलाया जा रहा है। सबसे बुरी बात यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक विश्वास, उनके रीति-रिवाजों और आचरण-व्यवहार, उनकी खाने-पीने की आदतों पर और इस मामले में, उनके पूरे जीवन जीने के तौर-तरीकों पर हमला किया जा रहा है। उनके जीवन की न्यूनतम सुरक्षा खतरे में है। संक्षेप में यूं कहें कि जीने का उनका अधिकार ही घोर खतरे में है। दूसरी ओर, आम लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को व्यवस्थित रूप से विभिन्न तरीकों से कम किया जा रहा है। लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का तरह-तरह से हनन किया जा रहा है जो लोकतांत्रिक अधिकार आम लोगों ने बड़े संघर्षों के जरिये हासिल किए थे। विभिन्न जन आंदोलनों के जरिये लोगों ने जो लोकतांत्रिक अधिकार हासिल किए थे, जो मौलिक अधिकारों के रूप में माने जाते थे–जैसे संगठन बनाने, सभा, जलसे-जुलूस, प्रदर्शन करने, अपना मत प्रकट करने, जन आन्दोलन करने के अधिकार को व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से धीरे-धीरे छीन लिया जा रहा है। इन कृत्यों को फासीवाद के अलावा और क्या कहा जा सकता है? मजदूर-कर्मचारियों के लोकतांत्रिक आंदोलनों पर भी तरह-तरह के हमले चल रहे हैं। मजदूर आंदोलन संगठित करना बेहद मुश्किल होता रहा है। कल-कारखाने बंद होते जा रहे हैं। जो कुछ अभी भी चल रहे हैं, उनमें से भी ज्यादातर कल-कारखाने कर्मचारियों को कम वेतन के साथ अनुबंध के तहत लेकर चल रहे हैं। मजदूरों को मामूली सा जितना कुछ वेतन मिलता है, उसमें परिवार का गुजरा होना तो दूर रहा, उससे खुद का जिन्दा रहना भी मुश्किल है। महान कार्ल मार्क्स ने कई साल पहले पूंजीवाद के तहत उजरती गुलामी की बात कही थी। लेकिन आज मजदूर वर्ग का किया जा रहा पूंजीवादी निर्मम शोषण-उत्पीड़न मध्ययुगीन दास समाज जैसे एक समाज की याद दिला देता है।

आरएसएस-बीजेपी द्वारा दिया जा रहा है सांप्रदायिक-फूटपरस्त सोच-विचारों को बढ़ावा

लेकिन इससे भी अधिक खतरनाक बात यह है कि जब जाति, पंथ, धर्म और भाषा से ऊपर उठ कर वर्ग चेतना के आधार पर मजदूरों के बीच एकता पैदा करना प्रमुख आवश्यकता है, तब पूंजीपति वर्ग और उनकी ताबेदार सरकारें जाति, पंथ, भाषा, वंशमूल और धर्म के नाम पर नुकसानदेह फूटपरस्त विचारों और भावनाओं को बढ़ावा देने जैसे जघन्य साधनों का सहारा लेकर उस एकता को तोड़ने और भ्रातृघाती दंगे-फसादों में मेहनतकश लोगों को उलझाने की कोशिश कर रही हैं।

आप इतिहास के इस सबक से वाकिफ ही हैं कि निहित स्वार्थी हलकों द्वारा निश्चित तौर पर उकसाये बिना, मेहनतकश लोग फूटपरस्त मानसिकता को नहीं पालते हैं। इसकी बजाय, मालिक पूंजीपतियों के शोषण के खिलाफ एकता और एकजुटता की भावना उनके बीच कायम रहती है। लेकिन पूंजीपति वर्ग और उसकी ताबेदार राजनीतिक पार्टियां अपने मनहूस स्वार्थ में चालाकी से हर प्रकार के फूटपरस्त सोच-विचारों, संकीर्ण तबकाती और सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को मन में कूट-कूट कर भरते रहते हैं।

शासक पूंजीपति वर्ग और उसकी राजनीतिक पार्टियां, खासकर अब सरकारी सत्ता में बैठी बीजेपी सांप्रदायिकता के जहर को दुर्भावनापूर्ण फैलाने में जिस मुस्तैदी से जुटी हुई है, इसे शोषणकारी पूंजीवादी शासन से अलगाव में नहीं देखा जा सकता है। इस स्थिति में देश के लोकतांत्रिक खयालात वाले लोगों को परेशान करने वाला सवाल यह है कि हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी कट्टर सांप्रदायिक ताकतें, जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ आजादी आंदोलन के दौरान अपना बदसूरत सिर उठाने में असमर्थ रही और आजादी आंदोलन का विरोध करने के कारण निंदा की पात्र थी, वे कैसे आजादी के बाद धीरे-धीरे ताकत बटोर सकी और ऐसी एक राक्षसी शक्ति में तब्दील हो सकी? पूरा देश अब आतंकित है।

एक तरफ तो घोर कट्टरपंथी सांप्रदायिक आरएसएस-बीजेपी गठबंधन पूंजीपति वर्ग के पूरे समर्थन से राजनीतिक तौर पर लगातार बलवान होता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ, उस राजनीतिक शक्ति के बलबूते पर वे इस तरह की अनिष्टकर गतिविधियों में बेखटके संलिप्त हैं, जिनकी सभ्य समाज में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उन्होंने लगभग सभी वैज्ञानिक तर्कसंगत विचारों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है, और उनकी सभी गतिविधियों के जरिये बेपरवाह ढंग से एक व्यापक मुस्लिम-विरोधी नफरत खतरनाक रूप से उभर कर सामने आ रही है।

आप इस बात पर गवाह हैं कि कैसे मुस्लिम लोगों के अपने धार्मिक विश्वास को मानने के अधिकार, खाने-पीने के अधिकार,

(शेष पृष्ठ 3 पर)

कॉ. असित भट्टाचार्य का भाषण ...

(पृष्ठ 2 का शेष)

कपड़े पहनने के अधिकार, रस्मो रिवाज मानने, आदत और आचरण करने के अधिकार पर हमले हो रहें हैं। यहां तक कि उनकी शारीरिक सुरक्षा और विचारों की आजादी भी खतरे में है। हर जगह, भगवां ब्रिगेड उनके खिलाफ एक के बाद दूसरा झगड़ा-फसाद करवाती जा रही है। जो लोग आज्ञा मानने से इनकार कर रहे हैं उन्हें निर्दयतापूर्वक यातना दी जा रही है और कत्ल तक भी कर दिया गया। ऐसी सुनियोजित हिंसा और निरंकुश फरमानों से कोई निजात नहीं मिल रही है क्योंकि ये सभी पूरी सरकारी शह पाकर हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं। तथाकथित हिंदुत्व के नारे लगाते हुए, आरएसएस केवल उपदेश ही नहीं दे रहा है बल्कि मुसलमानों को हिंदू धर्म को अपनाने के निर्देश भी जारी कर रहा है। हद दर्जे की स्वेच्छाचारिता है! यह है जो इक्कीसवीं सदी में विज्ञान के इस युग में हमें देखना पड़ रहा है। इस सब के माध्यम से प्राचीन भारत का क्या 'महान' पहलू दिखाई दे रहा है? हिटलरी फासीवाद और ऐसे बर्बर कृत्यों के बीच क्या अंतर है? कुछ विशिष्ट मामलों में, आरएसएस की गतिविधियां हिटलरी शासन के अत्याचार और क्रूरता को भी पार करती जा रही हैं। यही कारण है कि आरएसएस-बीजेपी का यह अनिष्टसूचक उदय सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है बल्कि मानव जाति को शर्मशार करने वाला एक घिनौना प्रयास है–विज्ञान और प्रगति के खिलाफ एक विनाशकारी उभार है।

सांप्रदायिकता-फूटपरस्ती के इस खतरे की ऐतिहासिक जड़

आप में से कई जानते हैं कि हमारे देश के आजादी आंदोलन में दो परस्पर-विरोधी धाराएं थी–एक समझौतापरस्त और एक गैर-समझौतावादी। महात्मा गांधी की अगुआई वाली धारा ने वास्तव में टाटाओं, बिड़लाओं, मफतलालों, गोयनकाओं आदि सहित राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के हितों की सेवा की थी। इसके उलट, आजादी आंदोलन के सशस्त्र क्रांतिकारियों के नेतृत्व में एक गैर-सझौतावादी धारा थी। बाद में इस गैर-सझौतावादी धारा का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र क्रांतिकारियों के पूर्ण समर्थन के साथ किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने गैर-सझौतावादी संघर्ष के माध्यम से इस धारा ने आजादी आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी। यहां तक कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री रॉबर्ट एटली को भी इस सत्य को मान्यता देनी पड़ी थी। इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग के वर्ग हित की ताबेदार पार्टी के रूप में उभरी थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह पतनोन्मुख मरणासन्न पूंजीवाद का दौर था। इस दौर में, पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग की क्रांति की भय ग्रंथी से त्रस्त था। इसलिए, अब साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ पूंजीवाद एक क्रांतिकारी भूमिका निभा ही नहीं सकता था, उल्टे, इसने साम्राज्यवाद और सामंतवाद के साथ समझौता करना शुरू कर दिया था। विश्व पूंजीवाद का अभिन्न अंग होने के नाते भारतीय राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग ने सामंती चिन्तन-विचारों, धार्मिक अंधविश्वास, मिजाज, रुचि-संस्कृति, फूटपरस्त मानसिकता और धर्मान्धता के साथ समझौता करने का मार्ग भी चुना। इतना ही नहीं। यह ऐसे पिछड़े प्रतिगामी सोच-विचारों को भी संरक्षित और पोषित कर रहा था, ताकि जब सत्ता में बैठ जाए, तो वह अपने वर्ग शासन-शोषण को बनाए रखने के लिए उनका फायदा उठा सके। धर्मनिरपेक्षता की सच्ची भावना पैदा करना या संकीर्ण हिंदू-मुस्लिम मानसिकता से ऊपर उठना तो दूर रहा, समझौतापरस्त भारतीय राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में पनपा और विकसित हुआ। इन सभी विशेषताओं और घटनाओं की व्याख्या कर समझाते हुए, इस युग के अन्यतम प्रमुख मार्क्सवादी विचारक और एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के संस्थापक महासचिव कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा था कि यद्यपि ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन से राजनीतिक आजादी हासिल करने के लिए भारतीय लोगों की एक सतही राजनीतिक एकता तो विकसित हुई, मगर सांस्कृतिक रूप से वे कई तरह से बंटे ही रह गए। आजादी आंदोलन में महात्मा गांधी की अगुवाई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समझौतावादी धारा का यह अनिवार्य परिणाम था। यह इतिहास है। दूसरी तरफ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुआई वाली गैर-समझौतावादी धारा ने जाति, पंथ, क्षेत्र, नस्ल, धर्म और भाषा से ऊपर उठ कर लोगों को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर एकजुट करना चाहा था। इस धारा ने सच्ची देशभक्ति से लोगों को लैस किया था। आजादी आंदोलन में इस गैर-समझौतावादी धारा के कारण हिंदू महासभा आदि उस समय सांप्रदायिकता और अन्य विभाजनकारी मानसिकताओं का जहर फैलाने में सफल नहीं हुई थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन में यही गैर-समझौतावादी धारा उस समय की वामपंथी धारा के रूप में मानी जाने लगी थी। अंकुरित हो रहे इन वामपंथी सोच-विचारों के कारण, न तो धर्म पर आधारित देश के विभाजन के लिए इसके उकसावे के साथ सांप्रदायिक मुस्लिम लीग अपना मनहूस सिर उठा सकी थी और न ही सांप्रदायिक हिंदू महासभा और आरएसएस। उस समय, ये सांप्रदायिक ताकतें वास्तव में महत्वहीन थीं।

आजादी के बाद भी कांग्रेस शासन ने बरकरार रखी सांप्रदायिक-फूटपरस्त मानसिकता

लेकिन आजादी के बाद के भारत में शासक पूंजीपति वर्ग की पसन्दीदा पार्टी कांग्रेस ने सत्ता संभाली और धर्म, क्षेत्र, जाति, पंथ, नस्ल और भाषा के आधार पर आम लोगों को बांटने के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। इसने सांप्रदायिकता और विभिन्न विभाजनकारी विचारों को मिट्टी पर मजबूती से जड़ जमा लेने का मार्ग प्रशस्त किया। कांग्रेस के इस दृष्टिकोण का लाभ उठाते हुए और शासक पूंजीपति वर्ग के खुले समर्थन से, आरएसएस और इसकी राजनीतिक विंग, पूर्व जनसंघ और अब नाम बदलकर भाजपा ने ताकत हासिल करनी शुरू कर दी। पतनोन्मुख मरणासन्न पूंजीवाद के इस युग में, कांग्रेस भी, हालांकि खुले तौर पर ऐसा नहीं कहते हुए, उसने हिंदुत्व को अपने राजनीतिक घोषणा पत्र में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इस्तेमाल किया था और घोर सांप्रदायिक ताकतों के साथ किसी भी संघर्ष से परहेज किया था। नतीजतन, सरकारी सत्ता संभालने के तुरंत बाद, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आने लगा। चुनावी लाभ बटोरने के उद्देश्य से, कांग्रेस देश के विभिन्न हिस्सों की अनिवार्यताओं के अनुसार सांप्रदायिक और फूटपरस्त ताकतों के साथ समझौता करने और तालमेल करने लगी और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस-बीजेपी को ताकत जुटाने में मदद दी। यह आजाद भारत के पिछले 70 वर्षों का इतिहास है। इसलिए, जो लोग कांग्रेस को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं वे या तो अज्ञानी हैं या सफेद झूठ बोलते हैं या उनकी रग-रग में चालाकी है। वे गूढ़ अभिप्राय से इतिहास को तोड़-मरोड़ते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इसके परिणामस्वरूप, महत्वपूर्ण तथ्य अस्पष्ट हो रहा है कि सत्ता में बैठने के बाद कांग्रेस अपने चुनावी स्वार्थ में हिंदू-मुसलमानों के बीच दरार और फूट डाल रही है।

क्या है वामपंथ?

अगली बात जो मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि हमारे आजादी आंदोलन के दौरान वामपंथी धारा ने आरएसएस और हिंदू महासभा को महत्वहीन बना दिया था और उन्हें अगली कतारों में आने नहीं दिया था–उन परास्त कर दी गई सांप्रदायिक ताकतों का पुनरुत्थान आजादी के बाद के भारत में कैसे संभव बनाया जा सका जबकि विभिन्न राजनीतिक दल खुद के वामपंथी होने का दावा करते हुए अत्यंत सक्रिय हैं? आजादी के बाद के भारत में खुद को वामपंथी घोषित करने वाले लोग इन सांप्रदायिक और धार्मिक कट्टरपंथी ताकतों का प्रतिरोध करने में उचित भूमिका निभाने में नाकाम क्यों रहे? यह नाकामी सच्चे वामपंथ का नतीजा है या नकली वामपंथ का? सही उत्तर पाने के लिए, हमें स्पष्ट रूप से यह समझना होगा कि वामपंथी चिंतन-विचारों का क्या अर्थ है और सच्चे वामपंथ की मर्मवस्तु क्या है। हमारे प्रिय नेता और इस युग के अन्यतम श्रेष्ठ मार्क्सवादी चिंतनकार कॉमरेड शिवदास घोष ने बार-बार इस मुद्दे पर प्रकाश डाला था। उन्होंने दिखाया था कि मुट्ठी भर शोषकों और असंख्य शोषितों के बीच विभाजित इस समाज में वे राजनीतिक ताकतें जो यथा स्थिति बनाए रखने के पक्ष में हैं, इसका मतलब है कि जो लोग शोषकों और शोषणकारी प्रणाली के खिलाफ वास्तविक भूमिका नहीं निभाते हैं, जिनकी राजनीतिक गतिविधियां मौजूदा प्रणाली की स्वीकृति पर आधारित हैं, उनको वामपंथी नहीं माना जा सकता है। वे दक्षिणपंथी हैं। दरअसलं, वे इस शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था और शोषण की प्रक्रिया की रक्षा में शोषकों के गुर्गों के रूप में कार्य कर रहे हैं। और जो लोग वास्तव में यथा स्थिति के खिलाफ हैं, वे असली वामपंथी हैं। आजादी आंदोलन के दौरान मुख्य द्वंद्व शोषणकारी ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन और उस से मुक्त होने के लिए गैर-समझौतावादी संघर्ष के बीच था। जहां ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपने शोषणकारी शासन को बनाए रखना चाहता था, भारतीय लोगों को गुलाम बनाए रखना चाहता था–वहीं समस्त शोषित लोग आजादी पाना चाहते थे। ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन-शोषण के खिलाफ संघर्ष के दौरान, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में गैर-समझौतावादी धारा उभरी थी। संघर्ष की इस गैर-समझौतावादी धारा को उस समय की वामपंथी धारा के रूप में पहचाना गया है। यह वह धारा थी जहां जाति, पंथ, धर्म और भाषा के बावजूद आजादीपसन्द आम अवाम की व्यापक और गहन संभव एकता बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए थे। उस समय, फूट डालना नहीं बल्कि शोषित लोगों की एकता कायम करना वामपंथ का सार बन गया था।

आजादी के बाद, मुख्य द्वंद्व के सवाल के बारे में एक बुनियादी बदलाव हुआ। राजनीतिक आजादी हासिल करने के बाद, यह राष्ट्रीय पूंजीपति ही था जो नया शोषक बन गया। इस बदली हुई स्थिति की पृष्ठभूमि में वामपंथी किसे माना जा सकता है? एक तरफ, हम शासक-शोषक पूंजीपति वर्ग और उनकी ताबेदार राजनीतिक पार्टियों को पाते हैं, और दूसरी तरफ, 95 प्रतिशत शोषित लोगों को। देश में आजादी आने के बाद के दौर में, राजनीतिक क्षेत्र में यह मूल द्वंद्व या मुख्य राजनीतिक द्वंद्व है। इस पृष्ठभूमि में, जो यथा स्थिति के पक्ष में हैं और जो वास्तव में यथा स्थिति के खिलाफ हैं–यह निर्धारित करेगा कि आज कौन दक्षिणपंथी हैं और कौन वामपंथी हैं। हालांकि, इस बिंदु पर कोई भ्रम नहीं है कि यह केवल क्रांतिकारी पार्टी ही है जो पूंजीपति वर्ग के शासन-शोषण के खिलाफ एक क्रांतिकारी स्टैण्ड लेती है, और जो क्रांति के जरिये पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के संघर्ष का नेतृत्व करेगी। इस क्रांतिकारी संघर्ष की अगुआई करने वाली किसी भी अन्य पार्टी का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन क्या उन ताकतों या पार्टियों को वामपंथीं कहा जाए जिनका पूंजीवाद के क्रूर शोषण-शासन से कोई वास्तविक द्वंद्व नहीं है और मेहनतकश आम लोगों की जायज मांगों को मनवाने के लिए सही मायने में जन आंदोलन गठित करने में जिनकी कोई रूचि नहीं है? क्या केवल कुछ मांगों को उठाने से ही कोई एक वामपंथी बन जाता है? 'वामपंथियों' नामधारी और यहां तक कि कम्युनिस्ट होने का दावा करने वाली पार्टियों द्वारा की गई धोखाधड़ी की राजनीति के बारे में हमारे देश के लोगों को पर्याप्त अनुभव है।

यदि इस दृष्टिकोण से हम स्थिति का विश्लेषण करें तो, यह स्पष्ट हो जाएगा कि आजादी के बाद की अवधि में वामपंथी होने का दावा करने वाली पार्टियां जैसे कि सीपीआई (एम), सीपीआई, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक इत्यादि ने बुर्जुआ शासन के तहत चुनावों के माध्यम से कुछ राज्यों में सत्ता में आने से पहले पूंजीपति मालिकों के खिलाफ कुछ ट्रेड यूनियन आंदोलन गठित किये और कांग्रेस सरकार के खिलाफ मेहनतकश लोगों की मांगों पर यहां-वहां जनांदोलन खड़े किये, लेकिन ये भी संवैधानिक सुधारवादी सीमाओं के भीतर ही सीमित रह कर किए। उन्होंने जो भी किया और कहा उसमें पूंजीवादी शोषण के तथ्य के बारे में कभी भी उनकी चिंता परिलक्षित नहीं हुई। शोषक पूंजीपति वर्ग के साथ पूंजीवादी शोषण से तबाह 95 प्रतिशत लोगों का द्वंद्व, मुख्य द्वंद्व बन गया है, इस सोच के आधार पर उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को शोषित आम जनता के हित के इर्दगिर्द न तो पहले कभी केंद्रित किया, न ही आज वे ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया और कहा उसका नतीजा यह निकला कि पूंजीपति वर्ग के शासन-शोषण के तथ्य को अस्पष्ट कर दिया गया। पूंजीवादी शोषण की वास्तविकता को स्वीकार किए बिना कभी-कभी साम्राज्यवाद-सामंतवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए, उन्होंने वास्तव में पूंजीवादी शोषण-शासन को बचाने की कोशिश की और आज भी ऐसा कर रहे हैं। इस सत्य की आज स्पष्ट रूप से पुष्टि हो गई है। अपनी पूरी राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से वर्ग चेतना पैदा करने की बात तो दूर रही, इसकी बजाए उनकी गतिविधियों से जो स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है, वह है घोर सुधारवाद और संवैधानिकता। अतीत में जब उन्होंने यहां-वहां कुछ जन आंदोलन गठित किये थे, तो उन्होंने ये इस तरह से किये कि वे इन्हें सुधारवादी और संवैधानिक सीमाओं के भीतर टिकाये रखने के लिए उनकी डोर खींच सकें। आज, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियां बन कर रह जाने पर इन्होंने मेहनतकश लोगों के आंदोलन का रास्ता छोड़ दिया है, वे सबसे बड़ी समझौतापरस्त ताकत बन गई हैं। पूंजीवाद और शोषित लोगों के बीच मुख्य द्वंद्व के बारे में कुछ भी नहीं कहने से, कुछ नहीं करने से क्या कुछ संकेत नहीं मिलता है? क्या इससे यह प्रतिबिंबित नहीं होता है कि खुद को वामपंथी होने का दावा करते हुए भी वे जानी-पहचानी पूंजीवादी पार्टियों की तरह ही आचरण-व्यवहार कर रही हैं? आज सभी लोग देख सकते हैं कि अन्य बुर्जुआ दलों की तरह, उनकी राजनीतिक गतिविधियां असेंबली, संसद और संसदीय राजनीति के दायरे में ही सीमित हैं। स्पष्ट रूप से अन्य बुर्जुआ और पेटी-बुर्जुआ पार्टियों की तरह, यह यथा स्थिति के पक्ष में एक स्टैंड है। यह वास्तविकता, यह सत्य किसी भी तरह से ढका नहीं जा सकता है। जहां तक जनमुक्ति का सवाल है, हम बखूबी जानते हैं कि वामपंथ के चोले में दक्षिणपंथ की राजनीति और भी विनाशकारी है। यहां, मैं फिर से यह कहना चाहता हूं कि न केवल आजादी के बाद के दौर में, बल्कि आजादी आंदोलन के दौरान भी अविभाजित सीपीआई सच्चे वामपंथ के परचम को बुलंद रखने में नाकाम रही थी। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में आजादी आंदोलन की गैर-समझौतापरस्त धारा के साथ सहयोग नहीं किया, जिन्होंने उस समय के सच्चे वामपंथ का परचम बुलंद किया था। इसके विपरीत, जब महात्मा गांधी की समझौतापरस्त लाइन और नेताजी की गैर-समझौतापरस्त लाइन के बीच गहन संघर्ष कांग्रेस के भीतर चल रहा था, तो वे नेताजी के पक्ष में नहीं खड़े थे, बल्कि उन्होंने उनका विरोध किया था। उन्होंने 1942 के ऐतिहासिक 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' आंदोलन का भी जोरदार विरोध किया था। वे आजाद हिंद फौज द्वारा स्वतंत्रता के लिए चलाए गए क्रांतिकारी संघर्ष

(शेष पृष्ठ 6 पर)

मिड-डे मील कार्यकर्ताओं ने आन्दोलन की हुंकार भरी

भिवानी में विरोध प्रदर्शन करते हुए मिड-डे मील कार्यकर्ता

भिवानी (हरियाणा) : यहां दिनोद गेट स्थित प्रजापति धर्मशाला में एआईयूटीयूसी से संबद्ध मिड-डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता यूनियन की जिला प्रधान मीरा देवराला ने की और संचालन जिला सचिव राजबाला पालुवास ने किया।

राजबाला ने कहा कि मिड-डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा मिड-डे मील कर्मियों की मांगों के लिए लम्बे अर्से से संघर्षरत है। महेन्द्रगढ़ में शिक्षामंत्री के आवास पर यूनियन के अनिश्चितकालीन धरने पर आकर शिक्षामंत्री ने मेहनताने में 1000 रुपये महीना की बढ़ोतरी करने, साल में दो वर्दियां देने और छुट्टियों के पैसे न काटने का आश्वासन दिया था। आन्दोलन के दबाव में उन्हें यह ऐलान करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह मिड-डे मील कर्मियों के आन्दोलन की जीत है, हालांकि यह आंशिक जीत है। यह मिड-डे मील कर्मियों की साझी उपलब्धि है। इसके लिए मिड-डे मील कर्मियों को कोटि-कोटि बधाई देते हुए उन्होंने आह्वान किया कि जो बढ़ा हुआ मानदेय है, उसे अपने पल्ले बांध लें और बाकी मांगें पूरी करवाने के लिए आन्दोलन तेज करें।

मीरा देवराला ने कहा कि मिड-डे मील कुकों को मेहनताने के रूप में मिलने वाले मामूली से मासिक 3500 रुपये में इतनी महंगाई में परिवार का गुजारा नहीं होता है। मिड-डे-मील कर्मी सरकारी स्कीम के तहत जब अपनी सेवाएं सरकारी स्कूलों में प्रदान कर रही हैं, तो सरकार को उन्हें अपना श्रमिक-कर्मचारी भी मानना चाहिए। उनके योगदान का सम्मान करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना चाहिए और जीने लायक वेतन देना चाहिए। मिड-डे मील कर्मियों को न तो श्रमिक-कर्मचारी माना जाता है, न न्यूनतम वेतन दिया जाता है और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है। जबकि 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने सभी स्कीम वकर्रों को अनिवार्य रूप से श्रमिक का दर्जा देने, मासिक न्यूनतम वेतन 18000 देने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की सिफारिश की थी। लेकिन इनको केन्द्र व राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है। हरियाणा की मिड-डे मील कर्मी अपनी मांगों को लेकर सितम्बर 2018 में चण्डीगढ़ में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार को अपना मांग पत्र सौंपेंगी।

एआईयूटीयूसी, भिवानी जिला कमेटी के सदस्य कॉमरेड राजकुमार बासिया ने कहा कि 2015 और 2016 में दो बार देशव्यापी श्रमिक हड़तालों और 17 जनवरी 2018 को मिड-डे मील कार्यकर्ताओं समेत सभी स्कीम वर्करों की देशव्यापी संयुक्त सफल हड़ताल ने जीत की आधारशिला रख दी थी। फिर 11 नवंबर 2017 को संसद के सामने दिल्ली महापड़ाव इस संघर्ष में एक सहायक कदम था। फिलहाल जीत सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित रह गई। अगर एकता मजबूत होती, तो सरकारी कर्मचारी के दर्जे और 18000 रु. मासिक न्यूनतम वेतन की मांग ज्यादा नजदीक लगती। लेकिन 17 जनवरी की स्कीम वर्करों की साझी हड़ताल के बाद सीटू से संबंधित यूनियन ने इस साझी लड़ाई से अचानक बाहर जाकर 'अपनी ढपली-अपना राग' शुरू कर दिया और एकता को कमजोर कर दिया। 17 जनवरी की देशव्यापी साझी हड़ताल के बाद सभी 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बैनर तले साझा संघर्ष जारी रहता तो नतीजा और भी बेहतर होता। तब हरियाणा समेत प्रदेश सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार पर एक साथ भारी दबाव पड़ता और सभी प्रदेशों में एक साथ और भी बड़ी जीत होती। उन्होंने कहा कि आन्दोलन के सिवा बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

सभा को एआईयूटीयूसी, भिवानी जिला कमेटी के कोषाध्यक्ष कॉ. राजकुमार जांगड़ा और जिला प्रधान कॉ. रामफल ने भी संबोधित किया। सभा में सैकड़ों मिड-डे मील कार्यकर्ता शामिल हुई।

फसलों का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य धोखा है

–ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन

ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) ने केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों के साथ धोखा बताया और नकार दिया।

किसान संगठन के प्रदेश सचिव जयकरण मांडोठी ने 14 जुलाई को प्रैस के नाम जारी बयान में बताया कि यह दाम पुराने फार्मूले ए 2 + एफएल के आधार पर दिए गए हैं जिनमें जमीन का किराया व कर्ज का ब्याज लागत खर्च में नहीं जोड़ा जाता। किसानों की मांग थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को पुराने से नहीं बल्कि नए फार्मूले से सी 2 + एफएल फार्मूले के आधार पर दिया जाए जिसमे सब खर्च जोड़े जाते हैं। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य मोटे धान पर 590 रुपये, ज्वार पर 845, मक्का पर 520 रुपये, तुअर पर 1797 रुपये, मूंग पर 2267 रुपये, मूंगफली पर 1389 रुपये और सोयाबीन पर 1059 रुपये है जो बेहद कम है।

कॉ. जयकरण मांडौठी ने केन्द्र सरकार से मांग की कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिश लागू करने का अपना चुनावी वादा पूरा करे और इन दामों पर फसल खरीदना सुनिश्चित करे। सरसों और बाजरे की खरीद-बेच को बाजार के हवाले न करे। लागत खर्च पर 50% अधिक दामों के लिए आंदोलन तेज करने का किसानों से भी आह्वान किया।

एआईडीवाईओ स्थापना दिवस पर

बेरोजगारी, नशाखोरी, अश्लीलता एवं सांप्रदायिकता के खिलाफ जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित

मुरादाबाद : सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. अरूण कुमार सिंह

मुरादाबाद (उ. प्र.) में सभा आयोजित

26 जून को एआईडीवाईओ की जिला कमेटी द्वारा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित सभा की अध्यक्षता कॉमरेड रूबी खान ने की और संचालन संगठन के कॉमरेड मो. गोरी ने किया। सभा को मुख्य वक्ता के रूप में एसयूसीआईआई (कम्युनिस्ट) के केंद्रीय स्टाफ कॉमरेड अरुण कुमार सिंह ने संबोधित किया।

कॉमरेड अरुण कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा आज देश का युवा रोजगार के लिए दर-दर भटक रहा है। रोजगार देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की बजाए सरकार रोजगार छीन रही है। रिक्त पद भरने की बजाए खत्म कर रही है। रेलवे से लेकर अन्य बड़े-बड़े उद्योगों में नौकरियां कम हुई हैं। लाखों कारखाने बंद पड़े हैं, तो युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? बेरोजगारी की समस्या का कारण देश के नवयुवकों को समझना होगा। बिना समझे आप कुछ समाधान नहीं कर सकते। देश-प्रदेश की सभी सरकारें देश के नौजवानों को छल रही हैं, नये-सब्जबाग दिखा कर उन्हें ठग रही हैं, उनको नए-नए नारे देकर गुमराह कर रही हैं। देश के नवयुवकों को सचेत होकर दीर्घस्थाई आंदोलन चलाना होगा। तभी कुछ होगा।

सभा को जिन अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया, उनमें एसयूसीआई(सी) के उत्तर प्रदेश सचिव कॉ. पुष्पेंद्र, नसीम वारसी, शाह आलम, राजेश कुमार, अनुजा राजपूत, विकास सक्सेना, धर्मपाल सिंह सैनी, एआईडीवाईओ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरकिशोर सिंह, मंजू मेहता, श्याम सुंदर प्रमुख थे। वक्ताओं ने कहा कि एआईडीवाइओ पूरे देश में युवाओं की हर प्रकार की समस्याओं के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चला रहा है। इसे और भी ताकतवर बनाने की जरूरत है।

इस मौके पर दो प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किए गए। इनमें एक प्रस्ताव संगठन के कार्यकर्ता के भाई गुड्डू वारसी के साथ नागफनी थाने के दरोगा द्वारा दुर्व्यवहार के बारे में था जिसमें दुर्व्यवहार करने वाले दरोगा को बर्खास्त करने की मांग की गई। दूसरा प्रस्ताव शहर में ठेला, खोमचा, फड़ी, रेहड़ी-पटरी वालों को न उजाड़ा जाने से संबंधित था।

रेवाड़ी (हरियाणा) में जिला स्तरीय युवा सम्मेलन सम्पन्न

एआईडीवाईओ के बैनर तले जिला स्तरीय युवा सम्मेलन 23 जून को स्थानीय नेहरू पार्क में सम्पन्न हुआ। आधुनिक भारत के निर्माता राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर व महात्मा फूले जैसे महान समाज सुधारकों व शहीद भगत सिंह व नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों एवं आदर्शों को स्कूल पाठ्यक्रम में उचित स्थान देने की मांग की गई। इन मांगों के अलावा इस सम्मेलन में जो मांगें जोरशोर से उठाई गई, वे थीं : देश-प्रदेश में खाली पड़े सभी पदों पर अविलंब स्थाई एवं नियमित भर्ती की जाए। सभी को रोजगार दिया जाए। रोजगार मिलने तक सभी को सम्मानजनक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए। ठेकेदारी प्रथा बंद करो। केवल स्थाई एवं नियमित भर्तियां ही की जाएं। जुर्माने जैसी भारी भरकम प्रवेश परीक्षा फीस एवं आवेदन फीस लेनी बंद की जाए। शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापारीकरण एवं निजीकरण करना बंद किया जाए। शराब, नशाखोरी अश्लीलता एवं हिंसा के प्रचार-प्रसार पर रोक लगाई जाए। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में समाज सुधारकों एवं क्रांतिकारियों को उचित स्थान दिया जाए। उनके जीवन-संघर्ष को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। नीति-नैतिकता एवं उन्नत संस्कृति को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय युवा नीति तैयार की जाए।

सम्मेलन में नई कमेटी का गठन किया गया। इसमें कॉ. नरेश कुमार को अध्यक्ष, कॉ. रणबीर सिंह एवं कॉ. पवन कुमार को उपाध्यक्ष, कॉ. अजय सिंह को सचिव, कॉ. सन्दीप को सह सचिव, कॉ. राजेश कुमार को कोषाध्यक्ष एवं कॉ. महेश कुमार, कॉ. अमरदेव, कॉ. लालचंद, कॉ. धीरज कुमार, कॉ. योगेंद्र सिंह व कॉ. सुमेर कुमार को कार्यकारी सदस्य की जिम्मेवारी सोपी गई।

रेवाड़ी : बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एआईडीवाईओ कार्यकर्ता

सरकारी स्कूलों में बेरोकटोक पास करने की नीति के खिलाफ छात्र प्रदर्शन

नई दिल्ली में प्रदर्शन करते हुए एआईडीएसओ कार्यकर्ता

नई दिल्ली : ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेन्ट्स ऑर्गेनाइज़ेशन (एआईडीएसओ) की ऑल इण्डिया कमेटी द्वारा 21 से 27 जून 2018 तक स्कूलों में पास-फेल प्रणाली खत्म किए जाने के खिलाफ अखिल भारतीय विरोधसप्ताह का आह्वान किया गया। इसी कड़ी में 27 जून को एआईडीएसओ की दिल्ली राज्य कमेटी द्वारा संसद मार्ग पर एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों से आये छात्रों ने हिस्सा लिया। विरोध का अहम मुद्दा आठवीं तक बेरोकटोक पास करने की नीति और इसे वापस लेने में सरकारी आनाकानी और हो रही देरी रहा। प्रदर्शनकारियों को संगठन के दिल्ली राज्य अध्यक्ष प्रशान्त कुमार, उपाध्यक्ष राहुल सरकार, सचिव श्रेया सिंह व राज्य कमेटी सदस्यों ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन राज्य कमेटी सदस्य प्रियंका चौरसिया ने किया।

वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत जब से नो डिटेंशन पॉलिसी लागू हुई है, उसी समय से उनका संगठन इसका विरोध कर रहा है। इस नीति के लागू होने के बाद से शिक्षा के स्तर में और भी गिरावट हुई है। अधिकांश विद्यार्थियो को ठीक से पढ़ना-लिखना नहीं आता है। वे गणित के आसान से सवाल हल नहीं कर पा रहे हैं। आज आम जनता भी इस बात को समझ चुकी है और इसका विरोध कर रही है।

वक्ताओं ने अपने संगठन की तरफ से सरकार से अपील की कि इस विनाशकारी नीति को जल्द से जल्द वापस ले और साथ ही आम छात्रों व शिक्षाप्रेमी जनता से अपील की कि पहली कक्षा से पास-फेल नीति को पुन: लागू करने की मांग को लेकर जुझारू आंदोलन गठित करें।

महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ते अपराध पर सेमिनार

बुराड़ी, दिल्ली में सेमिनार को सम्बोधित करते हुए कॉ. एम. चौरसिया

दिल्ली : बुराड़ी इकाई की तरफ से महिलाओं व बच्चों पर बढ़ते अपराध, कारण व् समाधान विषय पर एआईडीवाईओ व एआईएमएसएस की तरफ से संयुक्त सेमिनार का आयोजन दीपमनी पब्लिक स्कूल में 1 जुलाई को किया गया। इसमें स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। वक्ताओं ने कहा कि सरकार युवाओं का नैतिक पतन की दलदल में फंसाने की कोशिश कर रही है ताकि वे तर्क न कर सकें और अन्याय का विरोध ने कर सकें। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दिन-रात अश्लील प्रसारण, गली-मोहल्लों में खुले हुए शराब के ठेके व खुलेआम बाजार में नशीले पदार्थों की उपलब्धता से यह साफ जाहिर है।एआईडीवाईओ दिल्ली राज्य उपाध्यक्ष कॉ. प्रभास ने युवाओं से आह्वान किया कि जब तक हम सांगठनिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनने वाली। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नारा जरूर दिया जा रह है लेकिन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं।

मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए एआईएमएसएस की दिल्ली राज्य सदस्य कॉ. शारदा दीक्षित ने बताया कि आज समाज अपने नैतिक पतन की तरफ बढ़ रहा है। आधुनिकीकरण और पश्चिमी सभ्यता के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है जिसका प्रभाव हमारे नवयुवकों पर भी पड़ रहा है। सरकार इसको कम करने की बजाय और बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आह्वान किया कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी जगहों पर इसका विरोध करना चाहिए।

पार्टी के लोकल कमेटी इंचार्ज कॉ मैनेजर चौरसिया ने भी अपनी बात रखी। कार्यक्रम का संचालन एमएसएस की बुराड़ी इकाई सदस्य कॉ. मौसम ने किया।

अंत में एआईडीवाईओ के लोकल कमिटी इंचार्ज कॉ महेंद्र द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन हरियाणा ने ज्ञापन सौंपा

रेवाड़ी (हरियाणा) : एआईयूटीयूसी से संबद्ध आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन हरियाणा ने 18 जून को रेवाड़ी शहर में जोरदार प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम अपना मांगपत्र उपायुक्त को सौंपा। सरकारी स्कूलों की तर्ज पर गर्मियों व सर्दियों की छुट्टियां लागू करने की मांग उठाई गई। आंगनवाड़ी नेत्रियों ने कहा कि हम भी हाड-मांस की बनी हुई हैं। हमारा भी सामाजिक जीवन है। बच्चों के साथ हमारी भी गर्मियों में छुट्टी की जाए। 30 अप्रैल को जारी किए गए सरकारी आदेश को संशोधित कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुशल और अर्ध कुशल श्रमिक का दर्जा दर्ज करने, महंगाई भत्ता, पीएफ और ईएसआई की मंजूरशुदा मांग समेत नया आदेश पत्र जारी करने की आवाज उठाई गई। जिला प्रधान तारा देवी ने बताया कि 27- 28 फरवरी व 1 मार्च को बड़े अधिकारियों और निदेशक हरियाणा से हुई बातचीत में आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया बढ़ाने, हर महीने शहर में 6000 रुपय और गांव 3000 रुपये किराया लागू करने, रिटायर होने पर 5000 रुपये मासिक पेंशन और पांच लाख रुपए एकमुश्त आर्थिक सहायता देने, बच्चों और महिलाओं को अच्छा गुणवत्ता वाला पोषाहार देने, आंगनवाड़ी केंद्र सरकार द्वारा बनाने, पेयजल, शौचालय, बिजली-पंखे आदी का इंतजाम करने, सहायिकाओं को कार्यकर्ता तथा कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर की पदोन्नति देने, समायोजन के स्पष्ट नियम बनाने, मुफ्त इलाज व अकाल मृत्यु होने पर 11 लाख रुपए मुआवजा देने, बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता सुनिश्चित करने, आईसीडीएस स्कीम अपग्रेड करने, निजीकरण पर रोक लगाने मासिक वेतन 7 तारीख तक बैंक खाते में डालने और वेतन स्लिप देने की मांगों पर आम सहमति हुई थी। इनके बाद 4 माह बीत गए हैं। लिहाजा सरकारी आदेश जारी कर इन्हें लागू किया जाए। सरकारी कर्मचारी बनाने के लिए प्रधानमंत्री से सिफारिश करने की भी मांग की गई।

रेवाड़ी: प्रदर्शन करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका

सभी ने उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत अन्य राज्यों के संघर्षों का भरपूर समर्थन किया। प्रदर्शन से पहले जिला के सभी ब्लॉकों से आंगनवाड़ी कर्मी नेहरू पार्क में इकट्ठी हुई। वहां एआईयूटीयूसी के कॉमरेड राजेंद्र सिंह, बलराम यादव ने संबोधित किया। धरने-प्रदर्शन का संचालन यूनियन की जिला सचिव कृष्णा यादव ने किया। राजेश्वरी यादव, मुकेश, माया, अरविंद्र, सजना, बिंदु, सुशीला, कमलेश, सुमन, मंजू रोहिल्ला, नीलम, संतरा, पूनम, सरोज, शारदा, प्रेम, राजेश, सुषमा, सरला आदि नेत्रियों ने भी बात रखी।

सोनीपत (हरियाणा) : एआईयूटीयूसी से संबद्ध आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका यूनियन की सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में 14 जुलाई को स्थानीय अम्बेडकर पार्क से कैबिनेट मंत्री कविता जैन के आवास पर प्रदर्शन किया और उन्हें मांग पत्र सौंपा। यूनियन की प्रदेश महासचिव पुष्पा दलाल, जिला प्रधान गीता देवी, शीला मौन और एआईयूटीयूसी के प्रदेश सचिव कॉ. हरिप्रकाश ने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया।

कॉ. हरिप्रकाश ने कहा कि दबाव में सरकार जिन मांगों को सरकार मानने पर सहमत हुई थी, उन्हें अभी तक लागू नहीं करना सरकार की मजदूर-विरोधी मंशा को उजागर करता है। हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन नागर ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली महिलाओं को मांगें पूरी करवाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा। यूनियन के प्रदेश महासचिव पुष्पा दलाल ने कहा कि सरकार ने गर्मी-सर्दी की छुट्टी देने का आश्वासन दिया था लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा कि आंदोलन तेज किया जाएगा। यूनियन की जिला प्रधान गीता देवी ने भी प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया।

सोनीपत: प्रदर्शन करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका

उ. प्र. राज्य का दो दिवसीय छात्र शिविर आयोजित

ढकवां, प्रतापगढ़ में आयोजित कैंप में छात्रों को सम्बोधित करते हुए कॉ. सचिन जैन

ढकवा, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) : यहां ऑल इंडिया डीएसओ उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के तत्वावधान में 28-29 जून को डॉ. बी.आर. अंबेडकर शिक्षण संस्थान में राज्य का दो दिवसीय छात्र शिविर आयोजित किया गया। इसमें जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया इत्यादि जिलों से छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। कैम्प के प्रथम सत्र में शिक्षकों व अभिभावकों ने भी भाग लिया। इसकी अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष कॉ. हरिशंकर मौर्य ने की और संचालन राज्य कार्यालय सचिव कॉ. यादवेंद्र ने किया। एसयूसीआई(सी), उत्तर प्रदेश राज्य सचिव कॉ. पुष्पेंद्र अतिथि के रुप में मौजूद थे। उन्होंने शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर विस्तार से चर्चा की और छात्रों के दायित्वों को भी समझाया। संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कॉमरेड सचिन जैन मुख्य वक्ता थे। उन्होंने छात्रों की बुनियादी समस्याओं पर चर्चा की और छात्र आंदोलन की उपलब्धियां भी गिनायीं। उन्होंने कहा कि आज बच्चों व छात्रों के अंदर मानवीय मूल्यबोध, सामाजिक भावना, मानव-चरित्र, नीति- नैतिकता, व वैज्ञानिक सोच विकसित करना वक्त की जरूरत है। भाजपा-नीत सरकारें धार्मिक कट्टरता, अवैज्ञानिक, अनैतिहासिक व दकियानूसी विचारों को पाठ्यक्रमों में जोर-शोर से ला रही है। शिक्षा के निजीकरण- व्यापारीकरण को बढ़ावा देने के लिए तमाम शिक्षा-विरोधी नीतियां ला रही है। आज छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में पुलिस कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। जनवादी, वैज्ञानिक व धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पद्धति की मांग को व्यापक पैमाने पर छात्रों के बीच ले जाना होगा और छात्र आंदोलन खड़ा करना होगा ।

कार्यक्रम को एआईडीएसओ, उत्तर प्रदेश राज्य सचिव कॉ. दिलीप कुमार, उमाशंकर यादव ने भी संबोधित किया। इसके बाद के चले सत्रों में खेलकूद, गीत-संगीत, 'शिक्षा-संस्कृति का गिरता स्तर व हमारी भूमिका' पर परिचर्चा इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंत में कॉ. शिवदास घोष पर रचित गीत गाकर कैंप का समापन किया गया ।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2018-2020
Posting at New Delhi PSO on 7-8 and 22-23 Fortnightly

कृषि उपजों के समर्थन मूल्य में वृद्धि बीजेपी का एक और जुमला

अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। पिछले चार वर्षों में, बीजेपी सरकार के प्रधान मंत्री ने देश के लोगों से कई वादे किए थे। कोई भी पूरा नहीं किया। इसलिए कोई भी नया वादा जन मानस पर अब कोई छाप नहीं छोड़ता है। हर तरह से शोषित-पीड़ित और वंचित होने के कारण सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ देश के मेहनतकश लोगों का विरोध बढ़ रहा है। उनमें भारी रोष व्याप्त है। लगातार किए जा रहे तरह-तरह के शोषण और अभाव को केन्द्र करके जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसानों पर थोंपे जा रहे शोषण-जुल्म के खिलाफ किसान आन्दोलन देश भर में जारी है। इसलिए सरकार बार-बार लाठी-गोली से उस आन्दोलन को कुचलती जा रही है। अब, अचानक अपने आपको किसान-हितैषी प्रदर्शित करने के लिए बीजेपी सरकार ने चावल और गेहूं सहित 14 फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है।

धान के दाम 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की है। नतीजतन, समर्थन मूल्य 1750 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। केवल 13 प्रतिशत अधिक। स्वाभाविक है कि इस वृद्धि को सरकार का वादा पूरा हुआ कहना मानना किसानों को मंजूर नहीं है। बीजेपी सरकार का चुनावी वादा यह था कि, डॉ. स्वामीनाथन की सिफारिश को मानते हुए सरकार खेती पर किसान के कुल लागत खर्च में 50% की वृद्धि कर समर्थन मूल्य तय करेगी। स्वामीनाथन ने कहा था कि इस मामले में, खेत में खेती के सभी खर्च जोड़ने होंगे। शारीरिक श्रम, भूमि के पट्टे की लागत और कर्ज उधार लेने के खर्च सहित अन्य सभी लागत इसमें समाहित हैं। लेकिन सरकार ने उन्हें ध्यान में नहीं रखा।

सरकार समर्थन मूल्य पर जिस मात्रा में धान और गेहूं खरीदती है, वह कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है। हालांकि ज्वार, बाजरा, राघी, मूंग दाल इत्यादि के लिए इस बढ़ी हुई कीमत की घोषणा की गई थी, इसकी राशि जरा ज्यादा होने पर भी, यूं कहा जा सकता है कि सरकार उन्हें बिल्कुल ही नहीं खरीदती है। इनके मामले में वृद्धि की ये घोषणाएं महज कागजी हैं और चुनावी झांसों के सिवा कुछ नहीं हैं। अधिकांश फसल खुले बाजार में बेची जाती है। वहां मूल्य पर नियंत्रण सरकार का नहीं, बल्कि आढ़तियों और व्यापारियों का है।

पूंजीपति वर्ग की राजनैतिक मैनेजर होने के तौर पर काम करने वाली कांग्रेस-बीजेपी की सरकारों ने उदारीकरण की नीति के नाम पर कृषि क्षेत्र को बड़ी पूंजी के मुनाफे के लिए खोल दिया है। उनकी मेहरबानी से पिछले कुछ दशकों से खेती के लागत खर्च में असामान्य रफ्तार से वृद्धि हुई है। बीज किसान के हाथों से बाहर चले गए हैं। बीज, खाद अर्थात् उर्वरक, कीटनाशक आदि सभी देशी-विदेशी एकाधिकारी पूंजी के नियंत्रण में हैं। उनकी बेहद ज्यादा मुनाफे की भूख मिटाने के लिए इन सब चीजों के दाम आकाश छू रहे हैं। किसानों को लागत खर्च जुटाने के लिए ऋण लेना पड़ता है। कई छोटे किसान बैंकों और सहकारी समितियों की विभिन्न जटिलताओं की वजह से बेहद ऊंची ब्याज दर पर सूदखोर महाजनों से ऋण लेने को मजबूर हो रहे हैं। कटाई और अनाज निकालने के बाद ऋण चुकाने के लिए और परिवार के गुजारे के लिए किसानों का सस्ते में अपनी फसल बेचने के लिए वे तकाजा करते हैं। जबकि सरकार जितने समर्थन मूल्य पर फसल खरीदती है, उस सरकारी खरीद और बिक्री राशि के भुगतान में भी काफी देरी करती है। आढ़ती और व्यापारी इसका फायदा उठाते हैं। वे कृत्रिम रूप से फसल की खरीद कम करके फसल के दाम गिरा देते हैं। किसान कम कीमतों पर फसलों को बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। सरकार ने मजबूरी में औने-पौने दामों में फसलों की इस सस्ती बिक्री को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए हैं? थोथे और झूठे वादों की झड़ी लगाने के बावजूद किसी भी सरकार ने किसानों की लाचारी में इस सस्ती फसल बिक्री को रोकने के लिए कोई कारगर कार्रवाई नहीं की। इसलिए बीजेपी के नेता और मंत्री इस फैसले को ऐतिहासिक बता कर चाहे अपनी पीठ जितनी भी थपथपाएं, इससे किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है।

2006 में स्वामीनाथन ने सिफारिश की थी। कांग्रेस सरकार ने 2013 में केवल 170 रुपये बढ़ाये थे। पिछले चार सालों में बीजेपी ने अपना भिक्षादान बढ़ाकर सिर्फ 40-80 रुपये कर दिया है। जबकि खेती के लागत खर्च में काफी वृद्धि हुई है। क्या इससे यह साबित नहीं होता है कि किसानों को लाभकारी दाम देने के मामले को लेकर चाहे कांग्रेस या बीजेपी किसी की भी सरकार को कोई चिंता नहीं है? असल में किसानों को सचमुच ही फसलों के लाभकारी मूल्य देना चाहती तो इस तरह की हेराफेरी न करके खेती के तमाम खर्चों का हिसाब-किताब लगा कर उनसे सही मायने में 50 प्रतिशत ज्यादा दाम तय कर सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती और खुले बाजार में भी किसानों को जिससे उतने दाम मिल सकें इसका इंतजाम करती। लेकिन किसी भी सरकार ने यह व्यवस्था नहीं की है। क्यों नहीं की? क्योंकि, ये पार्टियां और सरकारें मुंह से चाहे जितना भी किसान-हितैषी होने की बात कहें, असल में वे किसानों के हितों की रक्षा नहीं, बल्कि उनका असली उद्देश्य कृषिजनित मालों का कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े-बड़े व्यापारियों के स्वार्थों की रक्षा करना है। इसीलिए सरकार अरबपतियों के मुनाफे की वृद्धि दर बरकरार रखने के लिए आये दिन पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि कर रही है, जबकि वह फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाने की अनिच्छुक है।

अगर सरकार वास्तव में किसानों के हित को देखना चाहती, तो पहले यह देखती कि खेती का लागत खर्च कैसे कम किया जाए। उर्वरक, बीज, कीटनाशक, ट्रैक्टर आदि साजोसामान सहित कृषि में काम आने वाली सभी आवश्यक चीजों और उपकरणों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में छोड़ना किसी तरह मुनासिब नहीं है। इनको लेकर मुनाफा कमाने पर प्रतिबंध लगाना और उन्हें सरकार के हाथों में रखना जरूरी था। सिंचाई प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता थी। ज्यादातर किसानों को गहरे ट्यूबवेल मालिकों से महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ता है। सरकार ने लंबे अर्से से सिंचाई प्रणाली में सुधार पर कोई ध्यान नहीं दिया है। ये सब किए बिना ही, अचानक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला कर मामूली सा कुछ समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा कर देने से अगर किसानों की सभी जटिल और स्थायी समस्याएं हल होती, तो कभी की हल हो गई होती। किसानों के जीवन की समस्या को हल करना सरकार की मंशा नहीं है। इस साल के अंत में, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। बीजेपी जानती है कि देश भर के किसानों के मन में वंचित होने का गुस्सा बारूद का ढेर बन गया है। चुनाव में कुर्सी नीचे से खिसक भी सकती है। अतः, उनके गुस्से को शांत करने के लिए इस नए जुमले या धोखेबाजी का सहारा लिया है।

कॉ. असित भट्टाचार्य का भाषण ...

(पृष्ठ 3 का शेष)

के खिलाफ खड़े थे, जिसने अंततः ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था।

इस स्थिति में, हम मानते हैं कि इस पृष्ठभूमि, देश की वाम राजनीति के इस दुखद पहलू को सही-सही समझे बिना, न तो आरएसएस और बीजेपी जैसी फासीवादी शक्तियों के उदय का मुख्य कारण समझा जा सकता है, न ही उनका प्रतिरोध करने की सही लाइन निर्धारित की जा सकती है। जाति, पंथ, धर्म और भाषा का लिहाज किए बिना समस्त शोषित-उत्पीड़ित लोगों को उनकी ज्वलंत मांगों को हासिल करने के लिए एकजुट करने वाले सच्चे वामपंथी आदर्शों और उच्च नीति-नैतिकता के आधार पर जोरदार गैर-समझौतापरस्त जन आंदोलनों की गैर-मौजूदगी की वजह से ही आरएसएस-बीजेपी अपनी वर्तमान ताकत हासिल कर पायी है। साथ ही, आरएसएस-बीजेपी को लोगों से पूरी तरह से अलग करने के लिए इसकी घोर प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक विचारधारा के खिलाफ तमाम लोगों को शामिल करते हुऐ निरंतर वैचारिक संघर्ष चलाने की जरूरत है। इसके सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

राजनीति में हैं केवल दो खेमें

इस संबंध में मैं भारत की राजनीतिक पार्टियों की विशेषता बताने वाली कॉमरेड शिवदास घोष की एक मूल्यवान सीख का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक परिदृश्य में, कई अलग-अलग राजनीतिक पार्टियां हैं। लेकिन हकीकत में, केवल दो ही खेमे हैं। एक खेमे में हम उन लोगों को पाते हैं जो शोषण करने वालों के पक्षधर हैं—कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, सभी, यहां तक कि सीपीआई (एम) और सीपीआई भी—जो वस्तुतः पूंजीवादी व्यवस्था के आगे आत्म-समर्पण करके और बुर्जुआ संसदीय राजनीति की चारदीवारीं के भीतर बंद रह कर अपनी राजनैतिक गतिविधियां चला रही हैं। दूसरे खेमे में केवल एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) है जो शोषित लोगों के हित में पूंजीवादी शासन-शोषण के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने इस अर्थ में कहा कि हालांकि देखने को कई राजनीतिक पार्टियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन असल में, केवल दो ही खेमे हैं। एक तरफ, यह एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) है जो शक्तिशाली जन आंदोलन गठित करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है और क्रांतिकारी उद्देश्य के साथ इसके परिपूरक चुनाव में भी भाग ले रही है। संसद और विधानसभा के भीतर विकासशील वर्ग और जनसंघर्षों की आवाज को बुलंद करने के लिए क्रांतिकारी लोग एक निश्चित चरण तक चुनावों में भाग लेते हैं। लेकिन, सीपीआई (एम), सीपीआई ने नीति-नैतिकता और सिद्धांतों को ताक पर रख कर बुर्जुआ चुनावी राजनीति को अपना एकमात्र राजनैतिक घोषणा पत्र बना लिया है, और उस उद्देश्य के लिए किसी भी कीमत पर कुछ सीटें पाने के लिए सिद्धांतहीन चुनावी गठजोड़ में प्रवेश कर रही हैं। इस तरह, वे मौकापरस्त राजनीति की दलदल में डूबती जा रही हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इसके अनिवार्य परिणाम के रूप में, उनका अस्तित्व अब दांव पर है। साथ ही, जन आंदोलनों से मुंह मोड़ लेने वाली राजनीति पर अमल करने के परिणामस्वरूप, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक आज लगभग अस्तित्व में नहीं रहे हैं। सीपीआई (एम) और सीपीआई का अस्तित्व भी जन आंदोलनों से मुंह मोड़ लेने की ऐसी राजनीति पर अमल करने की बदौलत आज खतरे में है। वामपंथ को लगे इस झटके से खुश होने की कोई बात नहीं है। वास्तव में, यह गहरी चिंता का विषय है।

जनवादी जन आंदोलन गठित होने में बाधा

इस स्थिति में, यह भी गंभीर चिंता का विषय है कि जब समाज और सभ्यता की प्रगति के लिए अत्यधिक हानिकारक, घोर प्रतिक्रियावादी शक्ति ने ताकत हासिल कर ली है और एक फासीवादी खतरा पैदा कर रही है, जो पूंजीवादी लोकतंत्र में जो कुछ भी बचा है, उसे खतरे में डाल रही है, इस खतरनाक शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए जोरदार जनवादी आंदोलनों को खड़ा करना जोकि इतना महत्वपूर्ण है, वह बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। इसकी जो भी गुंजाइश थी, वह भी भरभरा कर तेजी से खत्म होती जा रही है, यहां तक कि आज यह निचले स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों और कैसे यह कमजोरी आ सकी। इस सवाल पर दो राय नहीं हो सकती हैं कि पूंजीवादी शासन और समस्त मेहनतकश आबादी के किए जा रहे शोषण के संदर्भ में वामपंथ अप्रचलित और अप्रासंगिक नहीं हो सकता है। इसकी बजाय, वामपंथी आंदोलन और भी अधिक अत्यावश्यक हो गया है। तब यह संकट क्यों? हमें वैज्ञानिक वस्तुपरक विश्लेषण से जवाब पाना है। विज्ञान हमें बताता है कि जो कुछ भी होता है उसका एक निश्चित कारण होता है। यहां भी मामला सुनिश्चित तौर पर यही है। वामपंथी विचारधारा का मतलब न तो कोई विशेष पार्टी है, न ही यह पार्टीरहित हो जाना है—पार्टी तो उसकी वाहक है। आपने निश्चित रूप से देखा है कि सीपीआई (एम) और सीपीआई जैसे वामपंथी पार्टियों के रूप में जानी जाने वाली पार्टियां धीरे-धीरे वैचारिक और संगठनात्मक रूप से महत्वहीन होती जा रही हैं। आरएसएस-बीजेपी के उभरने पीछे यह कारण नहीं हो सकता। सही वापंथी आंदोलन से महरूम माहौल में आरएसएस-बीजेपी ने ताकत जुटा ली है। आप में से कई जानते हैं कि पश्चिम बंगाल को एक समय वामपंथी विचारधारा और वामपंथी आंदोलन का गढ़ माना जाता था। इस पश्चिम बंगाल में, 34 वर्षों के निर्बाध शासन के बाद, सीपीआई (एम) को दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी कांग्रेस पार्टी से दोफाड़ होकर बनी तृणमूल कांग्रेस द्वारा सत्ता से हटा दिया गया था, जो वामपंथ-विरोधी, कम्युनिस्ट-विरोधी और अत्यधिक जोरशोर से सीपीआई (एम)-विरोधी नारे देकर आई थी। केरल में, किसी भी सिद्धांत से कोई सरोकार नहीं रखते हुए, बल्कि सभी सिद्धांतों को बलाए ताक रखते हुए, बारी-बारी से सरकार बदल जाती है। हर पांच साल के अंतराल पर या तो कांग्रेस-नीत सहयोगी दलों की भीड़ सरकार बनाती है या सीपीआई (एम)-नीत सहयोगियों की भीड़ सरकार बनाती है। जहां तक सिद्धांत और एजेंडा का संबंध है, इन दोनों गठजोड़ों के बीच बहुत कम अंतर मिलता है। इसी तरह, नैतिकता और सिद्धांतों का बहुत ही कम सम्मान करते हुए और सरासर शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सीपीआई (एम) त्रिपुरा में 30 वर्षों तक सत्ता में रही। वहां भी उन्होंने दिन-पर-दिन उसी तरह सरकार चलाई जैसे पूंजीवाद की ताबेदार कांग्रेस और अन्य पार्टियां अपने शासनकाल में शासन कर रही थीं और इस प्रक्रिया में पूरी तरह से भ्रष्ट और पुलिस-प्रशासन पर एकमात्र निर्भर होकर जनविरोधी होकर, सीपीआई (एम) लोगों का कोपभाजन हो गई थी। इसका फायदा उठाते हुए आरएसएस-बीजेपी जैसे घोर सांप्रदायिक ताकतों ने न केवल उच्च स्वर में सीपीआई (एम)-विरोधी बल्कि वामपंथ-विरोधी और कम्युनिस्ट विरोधी नारे बुलंद कर सत्ता हथिया ली है। आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं पाया जा सकता है, खास तौर से उन राज्यों में जो यह कहता हो कि वामपंथ के महान परचम को बुलंद रखने की वजह से सीपीआई (एम) ने इन दो राज्यों में सत्ता खो दी है। अन्य राज्यों में, सीपीआई (एम) एक महत्वहीन ताकत थी। लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कॉ. असित भट्टाचार्य का भाषण ...

(पृष्ठ 6 का शेष)

उनकी सरकारें लंबे समय से थीं। लेकिन इनके द्वारा इन राज्यों में सरकार चलाने के तरीके के कारण आप देखते हैं कि सत्ता में आने से पहले वामपंथी पार्टी के रूप में उनकी जो भी विचारधारात्मक अपील थी, वह आज शून्य हो गई है। उनकी पूंजीपतिपरस्त राजनीति के परिणामस्वरूप भ्रम-भ्रान्ति के गड़बड़झाले में पड़ कर वामपंथ और मार्क्सवाद की अपील भी, भले ही अस्थायी रूप से सही, धूमिल हो गई है। श्रम और पूंजी के बीच समझौतापरस्त भूमिका, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियों की मूलभूत विशेषता है, इन राज्यों में लंबे समय तक इनके द्वारा सरकारों के चलाने में साफ उजागर हुई है। इसके परिणामस्वरूप, वामपंथी विचारधारा और वामपंथ की ताकत दिन-प्रतिदिन कमजोर होती गई है और आरएसएस-बीजेपी समेत अन्य प्रतिक्रियावादी ताकतों ने जबरदस्त ताकत हासिल कर ली है। हालांकि, इसमें खुशी की बात नहीं है। क्योंकि, कुल मिलाकर यह वामपंथ और मार्क्सवाद पर एक गंभीर हमला है, भले ही अस्थायी हो। इसलिए, इसके मुख्य स्रोत और जड़ को खोजना समय का तकाजा है। यहां मैं याद दिला दूं जो कि महान साहित्यकार और विचारक शरतचंद्र चटर्जी ने अपने युगांतकारी उपन्यास 'शेष प्रश्न' में शानदार तरीके से कहा था। उन्होंने दिखाया था कि 'अच्छाई का दुश्मन उससे बड़ी अच्छाई के सिवा और कुछ नहीं होता है'- जिसका सार यह है कि वास्तव में जो अच्छा है, कोई विचार हो या कार्य, विकास के दौरान, और भी उच्चतर अच्छाई को जन्म दे सकता है। इसके अन्यथा नहीं हो सकता है। विज्ञान के निरंतर विकास में, हम इस सत्य की पुष्टि होती पाते हैं।

आरएसएस-बीजेपी को अपना मनहूस सिर उठाने में वामपंथी लाइन के ठुकराने ने की मदद

किसी भी क्षेत्र में सत्य निर्धारित करने के लिए, हर किसी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। यहां इच्छा या अनिच्छा का सवाल बिल्कुल नहीं उठता है। चूंकि विज्ञान हमें सिखाता है कि किसी भी घटना-परिघटना के पीछे सच्चाई की खोज करने के लिए विश्लेषण की पद्धति या प्रक्रिया का सही होना निर्णायक कारक है। वामपंथ सोचने की एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से विकसित सोच की एक श्रेणी है। यह सोच की दक्षिणपंथी प्रक्रिया से पूरी तरह से भिन्न है। यह दक्षिणपंथी विचारधारा को वैचारिक रूप से परास्त करके पैदा हुई है। विज्ञान के विकास के क्रम ने इस सच को उजागर कर दिया है कि एक विशेष विधि या एक विशेष प्रक्रिया किसी विशेष परिवर्तन की प्रकृति को निर्धारित करती है। विज्ञान के मामले में, हम देखते हैं कि ऑक्सीजन बनाने की विशेष प्रक्रिया केवल ऑक्सीजन ही उत्पन्न करती है न कि हाइड्रोजन। इसी प्रकार, हाइड्रोजन बनाने की विशेष प्रक्रिया में, केवल हाइड्रोजन ही बनता है न कि ऑक्सीजन। यहां मैं फिर से कॉमरेड शिवदास घोष की एक और मूल्यवान सीख की याद तरोताजा कराता हूं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के एक पहलू को समझाते हुए उन्होंने कहा था, "परिणाम दिखाएगा, क्या चीज क्या है।" कार्य-कारणता के नियम की समझ समान है। एक घटना का एक विशेष कारण होता है। किसी दूसरी घटना का कोई दूसरा कारण होता है। वैज्ञानिक रूप से किसी भी घटना-परिघटना का विश्लेषण करते समय हम विज्ञान के इस मौलिक सत्य को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषण के मामले में भी यही सच है। यहां फिर से मैं महान साहित्यकार शरतचंद्र के एक और प्रसिद्ध, बहुत मर्मज्ञ दावे का उल्लेख करना चाहता हूं। एक स्थान पर उन्होंने दृढ़ता से कहा कि 'कोई महान काम करने के लिए कुछ महान करने का बस मन और पवित्र इच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है'। हमारे महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष ने हमें बार-बार याद दिलाया था कि सत्य पर पहुंचने में प्रक्रिया या पद्धति की शुद्धता निर्णायक है या प्रमुख निर्धारक कारक है। दूसरी पार्टियों की जांच-परख करने या यहां तक कि हमारी अपनी गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए भी यही बुनियादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर चलने की जरूरत है। सीपीआई (एम) और उसके सहयोगियों ने केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा पर लंबे समय तक शासन किया है। हर मामले में, सत्ता में इनके कार्यकाल के अंत में ये दक्षिणपंथी राजनीतिक ताकतें ही सत्ता में लौट आई हैं। वे वामपंथ की उच्च समझ को जन्म नहीं दे सके थे और इसे सत्ता में नहीं ला सके थे। इस बारे में, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि किसी भी तरह किसी पर किसी ब्रांड का कोई लेबल चस्पा देने का हमारा इरादा नहीं है। इन राज्यों में हमारी गतिविधियां करते समय, हमने हर समय दिखाया है कि प्रशासन चलाने का उनका रोजमर्रे का ढर्रा या शैली पूरी तरह से वामपंथ से रहित है। उन राज्यों में जहां वे सत्ता में थे या वे सत्ता में हैं, उन्होंने पूंजीवादी शोषण के खिलाफ असंतोष से तड़फते 90-95 प्रतिशत मेहनतकश लोगों का साथ नहीं दिया। वे उनके साथ खड़े नहीं हुए और अभी भी जायज और न्यायोचित जन आंदोलनों के समर्थन में खड़े नहीं हैं। वे न केवल जनवादी आंदोलनों का विरोध कर रहे हैं और इस तरह के आंदोलनों को विकसित करने के रास्ते में बाधाएं पैदा कर रहे हैं, बल्कि सत्ता में रहते समय इन्होंने कांग्रेस या बीजेपी जैसी किसी अन्य पूंजीवादी पार्टी की तरह ही इन जनवादी संघर्षों को क्रूरता से कुचल दिया था। जिस वामपंथ की सीपीआई (एम) और सीपीआई बात करती हैं और जिस पर अमल करती हैं, वह सच्चे वामपंथ को संकट में डाल रहा है, जिससे वामपंथ को गहरा धक्का लग रहा है। उन्हें इसके अंजाम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उन्हें यह मानना होगा कि वामपंथ से रहित उनकी राजनीति का अनिवार्य परिणाम और वामपंथ के नाम पर पूंजीपति वर्ग की ताबेदारी ही नए रूप में दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी ताकतों के पुनरुत्थान और उभार का मूल कारण है।

हालांकि यह बड़े अफसोस की बात है, पर यह सच है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में, ग्रामीण इलाकों में उनके अनुयायियों और यहां तक कि उनके कुछ नेताओं ने पहले टीएमसी में पाला बदला था और अब वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। त्रिपुरा में भी यही बात हुई। वैज्ञानिक रूप से इस मुद्दे का विश्लेषण करते समय, इन कारकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सीपीआई (एम), सीपीआई जैसी पार्टियों के नेता-कार्यकर्ता जो वामपंथ में विश्वास करते हैं, जिनके पास अभी भी मार्क्सवाद-साम्यवाद की विचारधारा में भरोसा और विश्वास है, उन्हें इस मामले में गहराई से जांच-परख करनी होगी। उन्हें गहराई से यह समझने और अहसास करने की जरूरत है कि सीपीआई (एम) और उसके सहयोगियों के शासन के अंत में उनके नेतृत्व की गैर-वामपंथी राजनीति की वजह से घोर प्रतिक्रियावादी दक्षिणपंथी ताकतों का उदय अवश्यंभावी हो गया है, जिस नेतृत्व ने लंबे अर्से से वामपंथ को ठुकरा दिया था और जनआंदोलन का रास्ता छोड़ दिया था। इसलिए बुर्जुआ राजनीति और इनकी राजनीति में कोई फर्क नहीं पाया गया था। आप कृपया एक बात देखें। पूरे देश में आरएसएस-बीजेपी जैसी घोर प्रतिक्रियात्मक ताकतों के उभरने और भयानक सांप्रदायिकता की भयानक घुसपैठ हो जाने से अत्यावश्यक हो गया है कि जाति, पंथ, वंशमूल, क्षेत्र, भाषा, धर्म का लिहाज किए बिना सभी शोषित मेहनतकशों को एकजुट करके इस खतरे का प्रतिरोध किया जाए। लेकिन सीपीआई (एम) व सीपीआई के नेता आरएसएस-बीजेपी गठबंधन की जहरीली विचारधारा के खिलाफ सही वामपंथ के आधार पर शक्तिशाली विचारधारात्मक संघर्ष गठित करने की अपरिहार्यता के बारे में एक बार भी बात नहीं कर रहे हैं। इसकी बजाय, बीजेपी का प्रतिरोध करने के नाम पर बार-बार वे शासक पूंजीपति वर्ग की सबसे भरोसेमंद पार्टियों में से एक, कांग्रेस और ऐसी ही कुछ अन्य पार्टियों के साथ चुनावी एकता कायम करने की बात कर रहे हैं जबकि तथ्य यह है कि इसके कभी-कभी धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर होने के दिखावों के बावजूद, कांग्रेस ने कभी भी सच्ची धर्मनिरपेक्षता पर अमल नहीं किया। आजादी आंदोलन के दौरान भी सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए गांधी और जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेसी नेता जिस राष्ट्रवाद के हामी थे, वह हिंदू राष्ट्रवाद था।

आजादी के बाद भी सत्तारूढ़ हो जाने पर कांग्रेस कभी भी सरकार चलाने के लिए धर्म से ऊपर नहीं उठ पाई, इसने आरएसएस-बीजेपी के मुस्लिम-विरोधी नफरत अभियान के खिलाफ कभी वैचारिक संघर्ष नहीं चलाया। इसकी बजाय, चुनावी फायदा उठाने के लिए, इसने घोर सांप्रदायिक हिंदुत्व का समर्थन किया है और इस प्रकार बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इसने मंद-मंद सांप्रदायिक राजनीति की है।

इससे भी बदतर यह है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो उसने कभी भी आरएसएस-बीजेपी गठजोड़ द्वारा मुस्लिमों पर किये जा रहे सुनियोजित हमलों के खिलाफ कड़ा रवैया अख्तियार नहीं किया। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों ने कई मौकों पर बहुसंख्यकों की राजनीति के नाम पर सांप्रदायिक राजनीति पर अमल किया था। लेकिन विडंबना यह है कि आज आरएसएस-बीजेपी का प्रतिरोध करने के नाम पर सीपीआई (एम), सीपीआई उसी कांग्रेस के साथ एक चुनावी गठबंधन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। ये सभी साफ-साफ दिखाते हैं कि आज सच्चे वामपंथ से वे कितनी दूर हट गए हैं। हालांकि, इस अंधकारमय परिदृश्य के बावजूद जो अस्थायी है, हम दृढ़ता से मानते हैं कि सच्चे वामपंथ को एक बार फिर से उभर कर आने की जरूरत है। जनआंदोलनों के विकास के दौरान अपनी उच्च समझ के आधार पर सच्चे वामपंथ का पुनरुत्थान होना सुनिश्चित है।

सही मूल राजनीतिक लाइन के आधार पर निरंतर जनवादी आंदोलन का विकास

हम निराश न हों, हम हत्तोत्साहित न हों! यह याद रखें कि मेहनतकश लोगों के एकजुट निरंतर आंदोलनों के निर्माण के लिए, सच्चा वामपंथ और वामपंथी विचारधारा का कोई विकल्प नहीं है। अतः, वामपंथ का पुनरुत्थान ऐतिहासिक आवश्यकता है। इसलिए, सभी लोकतांत्रिक ख्यालात रखने वाले लोगों को संघर्ष के मार्ग में शामिल होने की जरूरत है। इस संदर्भ में, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जैसा कि अन्य क्षेत्रों में है, सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष को भी सही क्रांतिकारी पार्टी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ाया जा सकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि केवल एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) इस ऐतिहासिक कार्य को करने की तहेदिल से कोशिश कर रही है। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के अंतिम उद्देश्य के साथ जाति, पंथ, क्षेत्र, धर्म, वंशमूल और भाषा से ऊपर उठ कर शोषित लोगों को एकजुट करके शक्तिशाली सतत जनवादी आंदोलन गठित करने का निरंतर प्रयास कर रही है। यह भी एक तथ्य है कि असली वामपंथ का परचम अडिगता के साथ बुलंद करने और संघर्ष के मार्ग पर लगातार चलते रहने की वजह से, विभिन्न राज्यों के आम आदमी हमारी पार्टी के प्रति तेजी से आकर्षित हुए हैं। हम जानते हैं कि कोई भी रातोंरात मार्क्सवादी-कम्युनिस्ट चरित्र हासिल नहीं कर सकता है। इसकी निश्चित प्रक्रिया है जो विभिन्न चरणों और अवस्थाओं के माध्यम से गुजरती है। इस संबंध में यह याद रखें कि पहला और सबसे बड़ा कार्य हमारे देश के लोगों को वामपंथी विचारधारा की अपरिहार्यता के बारे में मनाना है। फिर उन्हें वाम जनवादी आंदोलन में शामिल कराने और जुटाने के लिए भरसक प्रयास किए जाने चाहिए। इस स्थिति में, हम हर जगह लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूंजीवादी शोषण-शासन के खिलाफ गैर-समझौतावादी संघर्ष की मूल राजनीतिक लाइन पर निरंतर जनवादी आंदोलन गठित करने हैं। असली वामपंथ को स्थापित करने का एकमात्र यही तरीका है। केवल इसी तरह से ही सांप्रदायिकता और विभिन्न प्रकार की फूटपरस्ती की जड़ें भी धीरे-धीरे उखड़ेंगी। आइए हमारे कंधों पर आयद इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ें।

मैं यहाँ अपनी बात समाप्त करता हूं।

इन्कलाब जिन्दाबाद!
एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) जिन्दाबाद!
सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष
लाल सलाम!

5 अगस्त...

(पृष्ठ 1 का शेष)

रफ्तार तेज कर रही है। हिंदू धर्मीय कट्टरता फैलाने के साथ सांप्रदायिकता, संकीर्णता, जातिवाद भड़काया जा रहा है। वोट बैंक के लिए शोषित-पीड़ित लोगों को बांटकर आपस में नफरत व कलह बढ़ाई जा रही है। फासीवादी साजिश के रूप में भाजपा पुरातनपंथी सोच-विचारों को पनपा कर समाज में बची-खुची वैज्ञानिक मनोवृत्ति व तर्कशील स्वभाव को नष्ट कर रही है। हालांकि इसका विरोध हो रहा है। इन फासीवादी साजिशों के खिलाफ किसान, मजदूर, छात्र-युवा एवं अन्य शोषित पीड़ित पुलिस की क्रूरता झेलते हुए भी जन जीवन की समस्याओं को लेकर स्वतः स्फूर्त संघर्ष के रूप में उठ खड़े हो रहे हैं। वक्त की जरूरत है कि इन संघर्षों को संयुक्त वामपंथी-जनवादी नेतृत्व में संगठित व संचालित किया जाए। परंतु दोहरे (सोशल डेमोक्रेटिक) आचरण के चलते सीपीएम और सीपीआई जुझारू जनसंघर्षों का पहले ही परित्याग कर चुकी हैं। मात्र चुनावी लाभ बटोरने के लिए ये कांग्रेस नीत गठबंधन की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष छतरी के नीचे जाने के लिए आतुर हैं।

दुनिया के हालात भी चिंताजनक हैं। विभिन्न देशों के पूंजीवादी शासक और साम्राज्यवादी एक-ब-एक लोगों पर बेहद आर्थिक बोझ लाद रहे हैं। सोवियत संघ के पतन के बाद आज दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बची है जो इन्हें रोक सके। इन हालात में अपने पिट्ठुओं का सहयोग लेकर अमेरिकी साम्राज्यवाद दूसरे देशों पर आक्रमण कर उनकी स्वतंत्रता व संप्रभुता को रौंद रहा है। ऐसी तनावग्रस्त राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्थिति में कॉमरेड शिवदास घोष के क्रांतिकारी विचारों से सुसज्जित एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) का अधिकाधिक ताकतवर उभार होना बहुत ही जरूरी है ताकि न केवल हमारे अपने देश में बल्कि पूरे विश्व के करोड़ों लोगों को सही दृष्टिकोण एवं संघर्ष का सही रास्ता प्रदान करने में अपनी भूमिका अदा करने में यह सक्षम बन सके।

कॉमरेड शिवदास घोष की 42वीं बरसी के मौके पर यह बात ध्यान में रखकर हमें पुनः संकल्प लेना होगा कि प्यार, ममता, स्नेह व सेक्स समेत जीवन के हर पहलू में चौतरफा संघर्ष संचालित करते हुए हम खुद को सच्चे क्रांतिकारी के रूप में ढालें। उन्होंने हमें बार-बार चेताया था कि यही एकमात्र विधि है जिसके द्वारा पार्टी को ताकतवर बनाने और अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाने के लायक बना जा सकता है। इसी समझ के साथ अपने फर्ज को निभा कर ही हम कॉमरेड शिवदास घोष को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2018-20
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 of every month, Fortnightly, Date of Publication : July 20, 2018

निर्भया सामूहिक बलात्कार व हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का

एआईएमएसएस ने किया समर्थन

दिल्ली के निर्भया बलात्कार मामले में उन्हें सुनाई गई मौत की सजा के फैसले की समीक्षा की मांग को लेकर की गई चार आरोपियों में से तीन की याचिका को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की अखिल भारतीय कमेटी ने समर्थन किया है। गत 10 जुलाई को जारी एक बयान में संगठन की दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड रितु कौशिक ने कहा :

चार आरोपियों की याचिका को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से पूरे देश के लोगों ने राहत की सांस ली है जो उत्सुकतापूर्वक यह देखने के इंतजार में थे कि जघन्य निर्भया काण्ड के अपराधियों को कब दंडित किया जाता है। यह देश के सभी सही सोचने वाले लोगों के संघर्ष की जीत है जिन्होंने दोषियों को दंड सुनिश्चित करने, इन्साफ दिलाने और नारी की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णायक और भावनात्मक लड़ाई लड़ी। पूरे देश ने अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग को लेकर इस जघन्य काण्ड का एक आवाज में विरोध किया था। इस अपराध की दुनिया भर में निंदा की गई थी। एक ऐसे समय जब हमारे देश में महिलाओं और बच्चियों पर अपराध खतरनाक दर से बढ़ रहे हैं, एआईएमएसएस दृढ़ता से मानता है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान निर्णय निश्चित रूप से हमारे देश में महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराधों और यौन हमलों का प्रतिरोधक सिद्ध होगा।

सभी संघर्षरत लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने सभी को भविष्य में भी इस देश में किसी भी महिला पर होने वाले हर जुल्म-अन्याय से लड़ने के लिए दृढ़संकल्पित और एकजुट रहने का आह्वान किया।

गुजरात में कच्छ विश्वविद्यालय में एबीवीपी के गुंडों द्वारा एक प्रोफेसर पर किए गए हमले की ऑल इण्डिया डीएसओ ने की कड़ी निंदा

एबीवीपी के गुंडों द्वारा 26 जून 2018 को गुजरात के भुज जिले में केएसकेवी कच्छ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर पर किए गए बर्बर हमले की छात्र संगठन ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स आर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) ने कड़ी निंदा की और दोषियों को उदाहरणमूलक सजा देने की मांग की।

ऑल इंडिया डीएसओ के महासचिव कॉमरेड अशोक मिश्रा ने 28 जून को बयान जारी कर एबीवीपी के गुंडों पर तुरंत कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की छात्र विंग एबीवीपी फिर से देश में अपना मनहूस सिर उठा रही है। एबीवीपी के गुंडों ने यूनिवर्सिटी सीनेट के चुनाव-2018 के संचालन के दौरान 'चुन-चुन कर मतदाता पंजीकरण फॉर्मों को अस्वीकृत करने' के निराधार बहाने एसोसिएट प्रोफेसर और रसायन विभागाध्यक्ष तथा चुनाव के संयोजक डॉ गिरीन ए बक्सी के मुंह पर कालिख पोत दी व उनको यूनिवर्सिटी कैम्पस में घुमाया। डॉ. गिरीन ए. बक्सी के चेहरे पर मली इस कालिख में कोई बहुत तेज किस्म का पदार्थ था और बहुत तीव्र जलन होने की वजह से प्रोफेसर को हस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना ने एबीवीपी के तथाकथित संस्कारी छात्र संगठन का असली चेहरा दिखा दिया है। यह कोई देश में ऐसी पहली घटना नहीं है। एबीवीपी के गुंडों द्वारा 26 अगस्त 2006 को माधव कॉलेज, उज्जैन के राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. एच. एस. सभरवाल पर छात्र परिषद के चुनाव रद्द करने पर कॉलेज परिसर में हमला किया गया था, जिनकी अगले दिन अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। 2008 में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रसायन विज्ञान की परीक्षा में पाठ्यपुस्तक से नकल करने से एबीवीपी के कुछ समर्थकों को रोकने पर महाराजा कॉलेज, उज्जैन के प्रिंसिपल श्री आशीष मेहता की बुरी तरह पिटाई की थी। मध्य प्रदेश के खांडवा में भागवंत राव मंडलोई एग्रीकल्चर कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा छात्रावास में रहने वाली एक लड़की के साथ कथित तौर पर अवैध संबंध होने के आरोप में उनके सहपाठी श्री अशोक चौधरी को जाहिराना तौर पर धुनाई कर डराया-धमकाया गया, तो श्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर को दिल का दौरा पड़ा था और 13 मार्च 2011 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अप्रैल 2014 में भाजपा के प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी कैम्पस में प्राणीशास्त्र के प्रोफेसर डॉ उमेश राय से एबीवीपी नेता ने बदसलूकी की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में 18 मार्च 2016 को 'भगत सिंह के जीवन और लेखन' पर प्रोफेसर चमन लाल की एक चर्चा-बहस को बाधित कर दिया था और उन्हें बुरे अंजाम भुगतने की खुली धमकी दी गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रसंता चक्रवर्ती को 22 फरवरी 2017 को एबीवीपी गुंडों ने पीटा था, क्योंकि उन्होंने रामजस कॉलेज में बातचीत रद्द किए जाने का विरोध करने वाले छात्रों का समर्थन किया था। इस साल जनवरी में, एबीवीपी के राष्ट्रीय सह-संयोजक करण पालसानिया ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मीनारायण से दुर्व्यवहार किया था क्योंकि उन्होंने उनके टेस्ट पेपर में 'पब्लिक विश्वविद्यालयों में भगवाकरण' के बारे में प्रश्न पूछा था।

उपर्युक्त घटनाओं से यह स्पष्ट है कि 'गुरु की पूजा करने वालों' का लबादा ओढ़े हुए एबीवीपी के कार्यकर्ता अपने सांप्रदायिक एजेंडा को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ वे उन शिक्षकों पर टूट पड़ते हैं जो उनकी मंशा के आगे अपना सिर नहीं झुकाते हैं। यद्यपि संघ परिवार 'भारतीय राष्ट्रवाद' के लिए कभी नहीं खड़ा हुआ, फिर भी आंदोलन की ताकत को खत्म करने, असंतोष की आवाज को दबाने और अन्याय का विरोध करने की संस्कृति को नष्ट करने के लिए 'राष्ट्रवाद' के छद्मभेष में एबीवीपी विश्वविद्यालयों में 'संस्थागत गुंडों' के रूप में काम कर रही है। 2014 में केंद्र में बीजेपी सत्ता में आने के बाद, एबीवीपी गुंडों को अपने किए की सजा का कोई डर नहीं रहा है। इसलिए, उनकी गुंडागर्दी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस पृष्ठभूमि में, एआईडीएसओ ने अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार और प्रशासन को मजबूर करने हेतु एक दीर्घकालिक जन आंदोलन गठित करने का देश के छात्रों, शिक्षकों, लोकतांत्रिक दिल-दिमाग वालों और शिक्षाप्रेमी लोगों से आग्रह किया।

समर कैंप

अंधविश्वास व अंधकार मिटाता है विज्ञान

नई दिल्ली : अंधविश्वास अंधकार की ओर ले जाता है और विज्ञान रोशनी की ओर। इसी उद्देश्य को लेकर पहल सांस्कृतिक मंच की ओर से 14 जुलाई को शालीमार बाग में एक दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया।

इसमें गिरवर सिंह और शुभा दीक्षित ने बच्चों को विज्ञान से रूबरू कराया।

एआईडीवाईओ स्थापना दिवस पर

बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ जगह-जगह प्रदर्शन, सभाएं

ए.आई.डी.वाई.ओ. के स्थापना दिवस 26 जून के अवसर पर देश भर में जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किये गए। बेतहाशा बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ उ.प्र. में बलिया में रेलवे मैदान से जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकाला गया। बदलापुर, जौनपुर स्थित पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाला गया जो इंदिरा चौक से होते हुए स.ब.इ. कालेज के नरसिंह बहादुर सभागार पर आकर सभा में तब्दील हो गया। 23 जून को डॉ. बी.आर.अम्बेडकर शिक्षण संस्थान ढकवा, प्रतापगढ़ में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई। 27 जून को शास्त्री घाट, वरूणा पुल, कचहरी, वाराणसी में हुई विचार-गोष्ठी की अध्यक्षता श्री रामकृष्ण वि.म.इ.का. के शिक्षक सुरेन्द्र प्रसाद ने की एवं संचालन एआईडीवाईओ के जिला संयोजक कॉ. कमलेश मौर्य ने किया। ''युवाओं के जीवन का लक्ष्य एवं हमारा कर्तव्य'' पुस्तक पढ़ी गयी एवं उपस्थिति लोगों ने उस पर अपने विचार रखे। संगठन के प्रदेश सचिव कॉ. मकरध्वज ने कहा कि 2014 के चुनाव में युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई भाजपा-नीत एनडीए सरकार ने भर्तियों पर रोक लगाकर एवं सभी पदों पर नियुक्ति का अधिकार ठेके पर देकर युवाओं को ठगने का कार्य किया है। सुलतानपुर : स्थापना दिवस के अवसर पर 26 जून को सब्जी मण्डी सिंहौली, कोइरीपुर, सुलतानपुर में एक गोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें जयप्रकाश मौर्य, राजेन्द्र मौर्य एवं राहुल मौर्य ने अपनी बात रखी।

बलिया

जौनपुर

जयपुर

ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने शहर में किया प्रदर्शन

महेंद्रगढ़ (हरियाणा) : एआईयूटीयूसी से संबद्ध ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा ने अपनी मांगों को लेकर 24 जून को शहर में प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने शिक्षा मंत्री के आवास पर जाकर ज्ञापन देना चाहा लेकिन पुलिस ने बेरीकेट्स लगा उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने भाजपा के जिला कष्ट निवारण कमेटी के सदस्य सुधीर दीवान को देवीलाल पार्क के पास ही ज्ञापन सौंपा।

ग्रामीण सफाई कर्मचारी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा पार्क में एकत्रित हुए। यूनियन के प्रधान जुगेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसके बाद सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारी बस स्टैंड, अग्रसेन चौक, मंडी रोड होते हुए आगे बढ़े। यूनियन के सचिव महेंद्र सिंह ने बताया कि इससे पहले भी हम विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप चुके हैं लेकिन सरकार हमारी मांगों के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है इसलिए हम आन्दोलन का रास्ता लेने पर मजबूर हुए हैं और मांगे हासिल करने तक यह आंदोलन जारी रहेगा।

पार्क में एआईयूटीयूसी की ओर से का. सुभाष चंद्र एडवोकेट, हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के महासचिव मास्टर सुबे सिंह और ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने सभा

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."
Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com फोन नं. : 011-25726631, 9868350503